Ok"k % 39(vad % 10 (vDVcj % 2017(eY; % nl #lk,

सीटू मजदूर

सीटू का ऐतिहासिक बंगलूरु चलो

राज्य अध्यक्ष वरालक्ष्मी 14 सितम्बर, 2017 को
बंगलुरू में मजदूरों की ऐतिहासिक रैली को संबोधित करते हुए

(रिपोर्ट पृ०10)

जन एकता जन अधिकार जनप्रतिरोध आंदोलन का अखिल भारतीय कन्वेंशन

(रिपोर्ट पृ० 6)

मावलंकर हॉल, नई दिल्ली; 18 सितम्बर, 2017

सीटू मजदूर

lhvkbVh;s dk e[ki=

अक्टूबर 2017

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

संयुक्त आंदोलन	5
राज्यों से	14
उद्योग व क्षेत्र	19
अंतर्राष्ट्रीय	23
कामकाजी महिला	25
उपभेक्ता मूल्य सूचकांक	26

सम्पादकीय

बढ़ता जनप्रतिरोध

,d vkj tc tu egurd'k lenk; ds fofHkUu rcdk ds thou vf/kdkj vkj ykdrkf=d] /keZfujis{k] l?kh; x.kjkT; Hkkjr ds ukxfjdk ds ukr lfo/kku esa of.kr vf/kdkj Hkktik ljdkjk vkj vkj,l,l fxjkgk ds geyk dh tn esa gS] rc] bu geyk ds f[kykQ turk dk çfrjks/k Hkh rsth ls c< jgk gS A

fiNys dqN eghuk esa n'k Hkj esa turk ds fofHkUu fgLlk dh vuqd lxfBr vkj Lor%LQwrZ dk;Zokfg;k gq;h gS A bues etnwj oxZ ds vknksyu] fdlkuk vkj [kr etnwjk ds vknksyu] Nk=k] ukstokuk vkj efgykvk ds vknksyu] nfyr] vkfnoklh] vYila[;dk ds vknksyu] vU; lkekftd lxBuk rFkk epk ds vknksyu] ldfpr gkrs ykdrs= ds fo#)] foosdh.k vkj oKkfud le>nkjh dh fgek;r esa] ljdkjh neu ds f[kykQ] rkuk'kkgkuk Qklhoknh #>kuk ds f[kykQ vknksyu 'kkfey gSA ;gh lc dke etnwjoxZ dh dk;Zlph esa 'kkfey gS A fiNys vdks dh rjg lhVw etnwj ds bl vd esa ge bues ls dqN cMs l?k"kZ dk 'kkfey dj jgs gS A

bldk ,d vU; egRoiw.kZ vk;ke ;g gS fd budh lekurk vkj lekof'krk vknksyu ds vuqd lk>s epk dh LFkkiuk ds :i esa mHkj dj vk;h gS A bu vknksyukRed epk dh nks cgqr yf{kr fn'kk;s gS A ,d] lekt ds lHkh vkfFkZd :i ls 'kkf"kr ,oa lkekftd :i ls mRihfM+r rcdk dh ,drk dk;e djus dh rhoz bPNk] tks vc dqN bykdk rd lhfer ugh jgh] cfYd yxkrkj pgqvkj rsth ls c<rh tk jgh gS vkj nwljh] fojks/k dks çfrjks/k esa cnyus vkj mlls vkxs c<krs gq;s ykdrs= dk vf/kdkj vkj 0;ogkj nksuks :iks esa okLrfod cukus dh gS A

dkjikjsV vkj lkEçnkf;d jkt ds bl vf/k;kjs le; esa Hkkjr ds etnwjoxZ ds fy;s ,d egku volj Hkh mifLFkr gqvk gSA fcuk etnwj oxZ ds dkjxj gLr{ks vkj Hkkxhnkjh ds egurd'k turk vkj ckfd;ksa ds ;s lxfBr vkj Lor%LQwrZ l?k"kZ vkxs ugh c< ldrsA blfy, gLr{ks vkj Hkkxhnkjh etnwjoxZ dh ,frgkfld ftEesnkjh gS A etnwjoxZ dh ,drk dks lokZPp çkFkfedrk ij ysdj vkj gj rjg ds ldh.krkoknh vkj voljoknh jq;s dks [kkfjt djds gh bl ,frgkfld nkf;Ro dks fuckgk tk ldrk gS A

lhVw ds ikl blds fy, oSpkfjd cfu;kn] jktuhfrd le>nkjh vkj lq;ä vknksyuks dks [kMk djus dk rjhdk gS A fdUrq bu vknksyuks esa Hkkx yuk Hkj dkQh ugh gS A ,s vknksyuks esa ijh çfrc)rk vkj lEi.kZ le>nkjh ds lkFk 'kkfey gksuk t:jh gS A

शोक संदेश

कॉमरेड सुबोध मेहता

वयोवृद्ध ट्रेड़ यूनियन नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कॉमरेड़ सुबोध मेहता के निधन पर सीटू सचिव मण्डल गहरे दुःख का इजहार करता है।

कॉमरेड सुबोध मेहता ने सीटू गुजरात राज्य समिति के महासचिव और बाद में इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह लंबे समय तक सीटू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे थे। वह राज्य के ट्रेड यूनियन और लोकतांत्रिक आंदोलनों के एक जाने–माने एवं सम्मानित नेता थे। कॉमरेड सुबोध मेहता ने सीपीआई (एम) की राज्य कमेटी के सचिव के रूप में भी काम किया और इसकी केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। सीटू उनके सभी साथियों और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

संसद में

बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक पर बोले तपन सेन

राज्य सभामें 10 अगस्त को, बैंक कर्जों की वसूली के लिए बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए सीटू महासचिव तपन सेन, सांसद ने कहा कि बैंकों के पैसे को, करदाताओं के पैसे को मारने वालों को 'नॉन परफार्मिंग असट्स' 'स्ट्रेस्ड असेट्स' व 'नॉन कोपरेटिव बोरोअर्स' जैसे सम्मानजनक नाम दिये जा रहे हैं। आर बी आई सार्वजनिक बयान दे रहा है कि वापस नही किये गये ऋणों' से निपटने के लिए बैंक 'केश कतरवा लें'। इसका मतलब है कर्जो को बट्टे खाते में डालना और करीब 3 लाख करोड़ के ऋण को बैंकों के खातों से हटा दिया गया है। विधेयक को निष्प्रभावी बनाने के लिए, सरकार, आर बी आई के जरिए बैंको को इस तरह से कर्जे वसूलने का रास्ता बता रही है ताकि बैंको को उत्तरदायी न ठहराया जा सके। आर बी आई बीच में क्यों आ रहा है ? तपन सेन ने पूछा। ऋणों की वापसी न होने से मुश्किल तो बैंकों को हो रही है।

कर्जों की वसूली के लिए केवल 12 कंपनियों के खिलाफ ही कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया है; संबंधित राशि 2.53 लाख करोड़ रूपये है, जो अनुमानित कुल एन पी ए का सिर्फ 25 प्रतिशत है। 80 प्रतिशत एन पी ए केवल 50 कंपनियों पर है। *''संप्रभु भारत सरकार जिसके पास संप्रभु अधिकार हैं इन 50 कंपनियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई नहीं कर सकती है''*, तपन सेन ने कहा। *''और वे कौन हैं ? वे मंत्रियों के विदेशी दौरों पर उनके साथ होते हैं। और इन विदेशी दौरो में व्यापार ठेके तय होते हैं, इजराईल व अन्य देशों की निजी कंपनियों के साथ।''*

एफ आर डी आई विधेयक लाया जा रहा है। इसे घाटे में आये बैंकों को खत्म कर देने के हिसाब से बनाया गया है। आर बी आई का डिप्टी गवर्नर हर दिन बोलता है कि हर चीज का 'पुनः निजीकरण' होना चाहिये। आज, आप कर्ज लिये बैठी कंपनियों के बाबत बैंको को इन्साल्वेंसी व बैंकरप्सी कोड का प्रयोग करने की ताकत देने की बात कर रहे हैं। कल एफ आर डी आई विधेयक, राष्ट्रीय कृत बैंकों सहित बैंकिंग कंपनियों के बारे में सरकार को इन्साल्वेंसी व बैंकरप्सी कोड़ का प्रयोग करने की ताकत दे देगा ''सेन ने कहा। टी के रंगराजन ने अपने संशोधन में सीधे हस्तक्षेप के बजाय आर बी आई की केवल सुपरवाइजरी भूमिका होने का प्रस्ताव किया। वसूली के लिए आर बी आई को कंपनियों का चुनाव नहीं करना चाहिये। जिनके विरूद्ध इन्साल्वेंसी व बैंकरप्सी कोड को प्रयोग में लाया जाना है उन्हें छांटने की जिम्मेदारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्म को निभानी है। तभी जवाबदेही स्थापित की जा सकती है और प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। अन्यथा, बस ये 12 कंपनियां ही होंगी; बाकी की 38 कंपनियां बच निकलेंगी। तपन सेन ने कहा कि स्टील सैक्टर गम्भीर संकट का सामना कर रहा है, लेकिन एक भी सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनी ने बैंकों को कर्जा वापस करने के मामले में कोई चूक नहीं की है। चार हजार करोड़ रूपये के नुकसान के बाद 'सेल' की स्थिति खराब है, लेंकिन उन्होंने बैंकों को ऋण का भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है। आप एअर इंडिया का पूरी तरह निजिकरण करने की तैयारी में हैं, लेकिन उन्होंने कर्ज वापसी के मामले में एक दिन की देरी नहीं की है।

इस मुद्दे को प्रभवी ढंग से संबोधित करने के लिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्राईब्यूनल (एन सी एल टी) का विस्तार करने व उसे मजबूत करने की तुरन्त आवश्यकता है, जिसके पास मामलों का अंबार लगाने से दिक्कतें आ रही हैं।

संयुक्त आंदोलन

सीटू का संसद के सामने 3 दिन के महापड़ाव का आह्वान

(9–11 नवम्बर, 2017)

दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 8 अगस्त के मजदूरों के सफल राष्ट्रीय कन्वेंशन के बाद *(सीटू मजदूर ; सितम्बर, 2017)* ; साझा मंच में शामिल सभी 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली कारपोरेटों की सरकार को उसके हमलों का प्रतिरोध करने और हकों व सामाजिक न्याय के संघर्ष को आगे बढ़ाने के देश मजदूरों के संकल्प के बारे में एक कड़ा संदेश देने के लिए संसद के सामने 9–11 नवम्बर तक 3 दिवसीय महापड़ाव का जोरदार आह्वान किया है।

आह्वान

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें देश के मजदूरों को, 8 अगस्त 2017 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए राष्ट्रीय संयुक्त ट्रेड यूनियन कन्वेंशन में उनकी शानदार भागेदारी के लिए हार्दिक बधाई और गहराई से प्रशंसा करती हैं। तालकटोरा स्टेडियम न केवल खचाखच भरा था, जहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी बल्कि जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे उतने ही उसके बाहर जमा थे। सभी सैक्टरों के मजदूर, संगठित व असंगठित, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र से, पुरूष व महिलाओं ने सारे देश जम्मू–कश्मीर से लेकर तमिलनाडु व केरल तक से मजदूरों ने बड़ी संख्या में कन्वेंशन में हिस्सा लिया।

घोषणापत्र में दर्ज कार्रवाई के आह्वान का जिस उत्साह व गर्मजोशी से मजदूरों ने समर्थन किया वह उनके काम के व जीवन के हालातों पर व कडे संघर्षो के बल पर प्राप्त किये गये ट्रेड यूनियन व श्रम अधिकारों पर मोदी सरकार के चौतरफा हमले का मुकाबला का उसे पीछे धकेलने के प्रति उनकी लगन का सुबूत है।

यह वक्त 8 अगस्त के राष्ट्रीय कन्वेंशन के आह्वान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस योजना तैयार करने का है। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें देश के समूचे मजदूर वर्ग से, भले ही उनकी संबद्धता कुछ भी हो, जमीनी स्तर पर अपनी एकता को मजबूत करने तथा 12 सूत्री मांगों पर संयुक्त अभियान को तेज करने का आह्वान करती हैं। उससे पहले राज्य, जिला, उद्योग स्तर पर संयुक्त कन्वेंशन, संयुक्त परचा वितरण, पोस्टरों व लामबंदी के माध्यम से मोदीनीत भाजपा सरकार को चेतावनी देने के लिए कि मजदूरों पर उसके हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, राष्ट्रीय राजधानी में 9–11 नवम्बर, 2017 के तीन द्विवसीय पड़ाव (घेरा डालो–डेरा डालो) को अभूतपूर्व ढ़ंग से कामयाब करने के लिए आगे बढ़ो। मजदूरों के संयुक्त संधर्ष को मजदूरों के और भी ताकतवर संधर्षों का और यदि सरकार ट्रेड यूनियन ओदोलन की उपेक्षा करे और अपनी विनाशकारी मजदूर विरोधी नीतियाँ जारी रखे तो अनिश्चितकालीन देशव्यापी आम हड़ताल समेत उनसे भी ज्यादा ताकतवर संधर्षों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिये।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें सारे देश के मजदूरों से, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच व मजदूरों व कर्मचारियों की स्वतंत्र फेडरेशनों के बैनर तले, तुरन्त ऐसे ताकतवर संधर्षों की तैयारी शुरू करने का आहवान करती हैं। हमारे पास खोने के लिए वक्त नहीं है।

इंटक, एटक, एच एम एस, सीटू, ए आई यू टी यू सी, टी यू सी सी, सेवा, एक्टू, एल पी एफ, यू टी यू सी

वर्गीय, जन व सामाजिक आन्दोलनों का अखिल भारतीय कन्वेंशन

जन एकता जन अधिकार आन्दोलन सीटू समेत 100 से भी ज्यादा वर्गीय, जन व सामाजिक संगठनों व आन्दोलनों के सांझे मंच के रूप में उभर कर आया है; सीटू की राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमलता इसकी राष्ट्रीय संगठन समिति में शामिल हैं। इस मंच ने 18 सितम्बर को नई दिल्ली के खचाखच भरे मावलंकर हॉल में एक अखिल भारतीय कन्वेंशन आयोजित किया।

कन्वेंशन ने तीन बुनियादी नारे पारित किये– जन एकता, जन अधिकार व जन प्रतिरोध (जनता की एकता, जनता के अधिकार व जनता का प्रतिरोध) कन्वेंशन ने कार्रवाईयों के कार्यक्रम के साथ जन घोषणापत्र पारित किया।

अखिल भारतीय कार्रवाईयों में 30 अक्टूबर को लोगों की एकता के सदेश के साथ जिला व निचले स्तरों पर – (1) सभायें/ जुलूस 'एकता मशाल' के साथ, एकता ज्योति, (मशालों या मोमबत्तियों के साथ) ; (2) सभी राज्यों, जिलों व निचले स्तरों पर मंच में शामिल सभी संगठनों व आन्दोलनों तथा राज्य स्तर पर इसके और विस्तार के साथ कन्वेंशनों का आयोजन ; (3) आयोजन समिति के फैसले के अनुरूप आगामी बजट सत्र के दौरान कार्रवाई के उच्च व अगले चरण का कार्यक्रम। कन्वेंशन ने 9–11 नवम्बर तक नई दिल्ली में होने वाले मजदूरों के अखिल भारतीय पड़ाव तथा 20 नवम्बर को किसानों के अखिल भारतीय संसद मार्च समेत मेहनतकश वर्ग के संयुक्त संघर्षो के प्रति समर्थन जाहिर करते हुए जन एकजुटता कार्रवाईयों का आह्वान किया है।

कन्वेंशन

मंच की समूची आयोजन समिति कन्वेशन के अध्यक्षमंडल में थी। एस. एफ. आई के महासचिव विक्रम सिंह ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया; एटक सचिव अमरजीत कौर ने कन्वेंशन की पृष्ठभूमि के बारे में बताया; ए आइ के एस (36 केनिंग लेन) के महासचिव हन्नान मोल्ला ने कार्रवाईयों के कार्यक्रम के साथ कन्वेंशन का घोषणापत्र प्रस्तुत किया; ए आइ के एस (अजय भवन) के महासचिव अतुल कुमार अंजान ने 24 सूत्री जन माँगपत्र पेश किया और एपवा महासचिव कविता कृष्णन ने घोषणापत्र व माँगों का समर्थन करते हुए अपनी बात कही।

आयोजन समिति के कई अन्य सदस्यों, विभिन्न वर्गीय व जन संगठनों, आंदोलनों के नेताओं ने भी घोषणापत्र, माँगपत्र, कार्रवाईयों के कार्यक्रम के समर्थन तथा आम व विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों के बारे में अपने विचार व्याक्त किये। सीटू की ओर से उसके उपाध्यक्ष जे एस मजुमदार बोले।

घोषणापत्र में चुनाव पूर्व किये गये वादों को पूरा न कर जनता के अलग–अलग तबकों पर मोदीनीती भाजपा सरकार के बढ़ते हमलों; राजनीतिक दलों को कारपोरेटों द्वारा पैसा दिये जाने समेत संस्थागत भ्रष्टाचार; किसानों की बदहाली, आत्महत्यायें, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की माँग करते किसानों की पुलिस द्वारा मौतें जैसे कि मैदसौर में; गरीब किसानों को कर्जमाफी से इंकार करने लेकिन पिछले 3 वर्षों में जानबूझकर बैंको का कर्जा न लौटाने वालों का 1.91 लाख करोड़ रूपया बट्टे खाते में डालने; एफ डी आई व ठेका कृषि के माध्यम से कृषि का निगमीकरण करने, जबरन भूमि अधिग्रहण, बड़ी संख्या में ग्रामीण गरीबों की बेदखली व विस्थापन; आदिवासियों व परंपरागत वन निवासियों के लिए वन अधिकार कानून का पालन न होने, एस पी टी/सी एन टी एक्ट को कमजोर करने; मनरेगा को कमजोर करने व उसका क्रियान्वयन न हाने; रोजगार, न्यूनतम वेतन व सामाजिक सुरक्षा के अभाव में खेतमजदूरों की बदहाली; बेरोजगारी की विकराल होती स्थिति; रोजगारों पर नोटबंदी व जी एस टी का बुरा असर तथा आधार से जोड़ने के नाम पर सामाजिक सुरक्षा से वंचित करने; मजदूरों की अधिकारों, आजिविका व श्रम कानूनों पर हमलें; सार्वजनिक क्षेत्र के निजिकरण की भारी मुहिम; स्वास्थ्य व शिक्षा का व्यावसायीकरण; दलितों व अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले; पशु व्यापार पर हमला कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने; राज्य द्वारा बर्बर दमन; गैर हिन्दी भाषियों पर हिन्दी थोपने; स्वतंत्र विदेश नीति को अमरीका की तरफ झुकाने; लगातार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा कुछ न करने, एल पी जी के दाम बढ़ाकर जनता को लूटने; वायदा करोबार और वस्तु विनिमय को प्रोत्साहन; पितृसत्तात्मक रवैये को बढ़वा दिये जाने व महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा तथा विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण; अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर हमला बोले जानें; संविधानिक प्रावधानों व जनतांत्रिक जगह के सिकुडने; आर एस एस व कट्टरपंथी विचारधारा तथा शिक्षा, संस्थानों व शासन के सांप्रदायिकीकरण के मुद्दों को सामने रखा गया। ऐसी परिस्थिति में कन्वेंशन ने *''तमाम वाम, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, तर्कशील, प्रगतिशील व खुले उदारमना लोगों से उनपर हो रहे हमलों का मुकाबला करने के लिए एक साथ आने का आहवान किया।''*

भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और देखभाल के अधिकार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन

ए.आर. सिन्धु

प्रो० प्रभात पटनायक कन्वेंशन को संबोधित करते हुए

''भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और देखभाल, में केन्द्र सरकार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं एवं उनसे आगे'' विषय पर 17 सितंबर को नई दिल्ली के पारसी अंजुमन हॉल में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन् करते हुए प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो० प्रभात पटनायक ने कहा कि भोजन, रोजगार, मुफ्त गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त गुणवत्ता की शिक्षा, बुढ़ापे की पेंशन और विकलांगों को लाभ की सार्वभौमिक हकदारी प्रदान करने के 5 बुनियादी अधिकारों की कुल लागत भारत के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 8% से 10% ही होगी। उन्होंने कहा कि इन बुनियादी अधिकारों, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हों, को मूलभूत अधिकारों के रूप में हासिल करने के लिए एकजुट संघर्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अमीरों पर कर लगाकर आसानी से से ऐसा कर सकती है, लेकिन वह बहुसंख्यक जनता के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हैं; अलबत्ता जनसंख्या के शीर्ष एक प्रतिशत के हितों वाली नीतियों को ही अपना रही हैं। इस तरह के संघर्षों में ट्रेड यूनियनों की अग्रणी भूमिका पर उन्होंने जोर दिया।

एनडीए सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में मूल सेवा प्रदाता व्यवस्था को नष्ट करने और निजीकरण के प्रयासों के संदर्भ में इस सम्मेलन का आयोजन सीटू से सम्बद्ध, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाडी वर्कर्स एंड हेल्पर्स (ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच), मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एम.डी.एम.डब्ल्यू.एफ.आई.), और ऑल इंडिया कोआर्डिनेशन कमिटी ऑफ आशा वर्कर्स (ए.आई.सी.सी.ए.डब्ल्यू.) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. की महासचिव और सीटू की राष्ट्रीय सचिव ए आर सिंधु, एम.डी.एम.डब्ल्यू.एफ.आई. की उपाध्यक्ष मोनिका दत्ता रॉय और ए.आई.सी.सी.ए.डब्ल्यू. की संयोजक रंजना निरुला की अध्यक्षता में, ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच की कोशाध्यक्ष अन्जु मैनी ने सम्मेलन में भाग लेने वालों का स्वागत किया। ए.आर. सिंधु ने सम्मेलन का घोषणा पत्र पेश किया। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में समस्याओं और संबंधित योजनाओं में मजदूरों की कामकाजी परिस्थितियों के बारे में ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच अध्यक्ष और सीटू की राष्ट्रीय सचिव ऊषा रानी, एम.डी.एम.डब्ल्यू.एफ.आई. के महासचिव जय भगवान और ए.आई.सी.सी.ए.डब्ल्यू. की सुरेखा द्वारा प्रस्तुत किया गया।

विभिन्न विषेशज्ञ पैनलिस्ट ने सरकारी नीतियों के साथ मुद्दों को जोड़ते हुए इन प्रस्तुतियों पर प्रतिक्रियाऐं दी। जन स्वास्थ्य अभियान के सह–संयोजक डॉ० अमित सेनगुप्ता ने स्वास्थ्य क्षेत्र की नीतियों को समझाया और कहा कि सिर्फ सबसे निचले स्तर पर इन महिलां मजदूरों का दावा ही समाज और व्यवस्था में 'ब्राह्मणवाद' की चुनौती को तोड़ सकता है। मोबाइल क्रैचज की देविका सिंह ने बोलते हुए समाज के लिए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व के बारे में और बच्चों के अधिकारों की लड़ाई से जुड़ी योजनाकर्मियों की लड़ाई के बारे में बताया। डॉ० रजनी पालड़ीवाला ने योजनाकर्मियों से जुड़ी जाति, लिंग और सामाजिक शोषण की व्याख्या की और कैसे उनकी लड़ाई वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देती है। उन्होंने जोर दिया कि आंदोलन को संघर्षों के भीतर विभाजनकारी ताकतों के प्रति जागरूक और सचेत होना चाहिए और साथ ही कार्यस्थल पर भी सभी तरह के भेदभाव से लड़ना होगा। भोजन का

अधिकार अभियान से जुड़ी दीपा सिन्हा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कानून के बावजूद विभिन्न सरकारें, योजनाओं को खत्म करने की कोशिश करती हैं और निजीकरण के लिए आगे बढ़ती हैं। उन्होंने समाज के साथ समन्वय करने और संघर्ष की सफलता के लिए उसे विश्वास में लेने के महत्व पर बल दिया। आर्थिक शोधकर्ता इंद्रनील मुखर्जी ने बताया कि भारत में बुनियादी सेवाओं पर खर्च बहुत कम है और हर साल 5.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया जाता है क्योंकि उनकी स्वास्थ्य देखभाल के खर्चे के कारण, जिसका बड़े पैमाने पर निजीकरण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बुलेट ट्रेन के लिए 1,11,000 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है, जिसका उपयोग पूरे साल में अधिकतम कुछ लाख लोगों द्वारा ही किया जाएगा, जबकि 60 लाख योजनाकर्मियों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के लिए केवल 1,08,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू. के अध्यक्ष थिरुनावक्करासु ने देश में खेत मजदूरों की स्थिति और उनके संघर्षों के बारे में तथा योजना कर्मचारियों के संघर्षों के साथ उनकी एकजुटता व्यक्त की। एसएफआई के संयुक्त सचिव मयूख बिस्वास ने एकजुटता व्यक्त करते हुए शिक्षा के निजीकरण को समझाया और लोगों की क्रय शक्ति के लगातार कम होने और देश में बेरोजगारी के बारे में बताया। बी.जी.वी.एस. की संयोजिका आशा मिश्रा ने बुनियादी सेवाओं के लिए लोगों के अधिकारों और उनकी 'पहुंच, गुणवत्ता और निष्पक्षता' के नारे पर उनके अभियान और कार्यक्रमों को समझाया। उन्होंने भोपाल में नवंबर के आखिरी सप्ताह में ए.आई.पी.एस.एन. के आह्वान पर योजनाकर्मियों को जन आन्दोलन में जुटने के बारे में बताया। सीटू के कोषाध्यक्ष एम एल मलकोटिया ने बताया कि योजना मजदूरों को संगठित करने और उनकी मान्यता के लिए संघर्ष करने के लिए सीटू के प्रयास लगातार रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप 45वें आई.एल.सी. की सिफारिशों की गयी जिन्हे 46वें आई.एल.सी. में भी दोहराया गया। उन्होंने कहा कि जिन तक नहीं पहुँचा गया उन तक पहुंचने और जनता मुद्दों के पीछे की नीतियों की उजागर करना है। एडवा की संयुक्त सचिव मेमूना मोल्लाह ने कहा कि इन योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में महिला आंदोलन और एडवा योजना मजदूरों का समर्थन और इन योजनाओं को मजबूत करने के लिए संघर्ष करेंगे। सी.डब्ल्यू.डी.एस., बल और एच. आर.एल.एन. ने भी योजना कर्मियों के संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त की।

कन्वेंशन ने तय किया कि (i) खाद्य, स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल के अधिकार की मूल सरकारी योजनाओं को बचाने के संघर्ष में लाभार्थियों और जनता के व्यापक वर्गों को शामिल करना है; (ii) मांगों पर संयुक्त रूप से जन प्रतिनिधियों और मंत्रियों से मिलना है; (iii) 9, 10, 11 नवंबर 2017 को संसद पर केन्द्रीय ट्रेड़ यूनियनों और कर्मचारियों के स्वतंत्र महासंघों द्वारा बुलाए गए तीन दिनों के धरने में योजनाकर्मियों को बड़ी संख्या में लामबन्द करना; और (iv) वामपन्थी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष वर्ग, जनता और सामाजिक संगठनों एवं व्यक्तियों के संयुक्त मंच, जन एकता, जन अधिकार मंच, के आह्वान में शामिल हों।

इस सम्मेलन में ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. और एम.डी.एम.डब्ल्यू.एफ.आई. के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों और हिंदी भाषी राज्यों से तथा आशा मजदूरों की यूनियनों के नेताओं ने भाग लिया था। अगर सरकार निजीकरण को रोकने को तैयार नहीं हैं, पर्याप्त बजट आवंटन, मजदूरों के रूप में मान्यता, न्यूनतम मजदूरी, पेंषन और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो योजनाकर्मियों को अभियान और संघर्श को तेज करने के लिए कहा गया। भोजन, स्वास्थ्य, षिक्षा और देखभाल के अधिकारों के लिए, आई.सी.डी.एस., एम.डी.एम.एस. और एन.एच.एम. को मजबूत करने की आवष्यकता पर जोर देने जनता के बीच हर संभव व्यापक अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

गौरी लंकेश की हत्या का विरोध

सीटू, पत्रकार, तर्कशील कार्यकर्ता गौरी लंकेश की आवाज को दबाने तथा विरोध करने वालों व अल्पसंख्यकों को भयभीत करने के लिए साम्प्रदायिक कट्टरवादी बंदूक धारियों द्वारा बंगलूरू में उनके धर के बाहर 5 सितम्बर को की गई उनकी हत्या के खिलाफ देशव्यापी विरोध में शामिल रहा।

गौरी लंकेश ने अपने पूरे व्यक्तित्व को स्वंय के द्वारा प्रकाशित व संपादित 'गौरी लंकेश पत्रिके' में जैसे विलीन कर दिया था; वे उसके माध्यम से आर एस एस व उसकी केसरिया पलटन की कारगुजारियों का पर्दाफाश करती थीं।

उनकी हत्या के विरोध में देश के विभिन्न भागों में स्वयंस्फूर्त विरोध आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसमें ट्रेड यूनियनों में संगठित मजदूरों सहित जनता के सभी तबके एक साथ आये। उनकी हत्या के ठीक अगले दिन, सीटू ने हत्या की निंदा करते हुए उसे सांप्रदायिक विभाजनकारी शक्तियों द्वारा गौविन्द पनसारे, नरेन्द्र डाभोलकर व एम एम कलबुर्गी की हत्याओं की श्रंखला की ही अगली कड़ी बताया; सीटू ने उनके परिवार व सहकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त की; तथा कर्नाटक सरकार से दोषियों को तुरन्त गिरफ्तार करने व

व साजिश को बेनकाब करने की माँग की; और देश के मजदूर वर्ग से इस जधन्य हत्या व धर्मनिरपेक्षता पर हमले के खिलाफ देशव्यापी विरोध करने का आहवान किया।

अगले सप्ताह, जीवन के सभी क्षेत्रों से हजारों लोग व जाने–माने व्यक्ति रेलवे स्टेशन से सेंट्रल कॉलेज तक *''मैं गौरी हूँ मार्च''* में शामिल हुए जो पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक दलों, मजदूरों, किसानों व अन्य के प्रतिनिधियों के प्रतिरोध कन्वेंशन में बदल गया।

विभिन्न तबकों का प्रतिनिधित्व करते हुए तीस जाने–माने व्यक्तियों ने कन्वेंशन को संबोधित किया इनमें कन्नड़ लेखक देवानुरू महादेव तथा चन्द्रशेखर पाटिल, सीताराम येचुरी, मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेष, प्रशान्त भूषण, पी.साईनाथ, तीस्ता सीतलवाड, जिग्नेश मेवानी, प्रो. गणेश डेवी, सागरिका घोष, सिद्धार्थ वरदाराजन, लेखक/ कार्यकर्ता नीलम के. कन्नड़ अभिनेता चेतन, कई प्रगतिशील मठों के महन्त शामिल थे। गांधीवादी व स्वतन्त्रता सेनानी एच एस दोराईस्वामी ने अध्यक्षता की।

उनकी हत्या के बाद, गौरी लंकेश पत्रिके के नये अंक को इस प्रतिरोध कन्वेंशन में जारी किया गया और यह एलान किया गया कि विरोध की आवाज के रूप में पत्रिके का प्रकाशन जारी रहेगा। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग; तर्कशीलों व कार्यकर्ताओं को निशाना बनाये जाने की साजिश की पड़ताल की मांग करते हुए तथा साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत पर एक प्रस्ताव भी कन्वेंशन में पारित किया गया।

दिल्ली में विभिन्न संगठनों, समूहों व शाखिसयतों द्वारा आयोजित सभा में भी सीटू, किसान सभा व एडवा शामिल रहे जिसमें 5 अक्टूबर को एक विशाल विरोध रैली करने का निर्णय लिया गया।

सीटू द्वारा पंजाब में विरोध

साम्प्रदायिक कट्टरपंथी ताकतों द्वारा बंगलुरू में पत्रकार गौरी लंकेश की जधन्य हत्या के विरोध में, पंजाब में सीटू ने रोपड व असरो औद्योगिक क्षेत्र में रैलियां निकाली व विरोध प्रदर्शन किये।

शान्तनु भौमिक की हत्या: बंगलुरू में गौरी लंकेश की हत्या के 15 दिन के अंदर ही त्रिपुरा में उग्रवादी समूह आई पी एफ टी द्वारा साम्प्रदायिक सदभाव के पक्ष में मजबूत राय रखने वाले एक स्थानीय समाचार चैनल के युवा पत्रकार शान्तनु भौमिक की हत्या कर दी गयी। इस हत्या के खिलाफ पत्रकार व जनता के अन्य तबके देशव्यापी विरोध में उतरे हैं। त्रिपुरा में सीटू के राज्य महासचिव शंकर प्रसाद दत्ता, सांसद अगरतला में हुए विशाल विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

राजस्थान में किसानों का ऐतिहासिक संधर्ष

राजस्थान में अखिल भारतीय किसाान सभा का 13 दिन लंबा किसान आंदोलन अपनी भारी जनभागेदारी, आंदोलन के स्वरूप, उपलब्धियों के हिसाब से ऐतिहासिक रहा। 1 सितम्बर को शुरू हुए आन्दोलन में 10 दिन तक अनिश्चितकालीन दिन–रात का महापड़ाव डाला गया और उसके बाद 20 जिलों के जिला कलेक्ट्रेटों पर जिलों, शहर–कस्बों को जोड़ने वाली सड़कों को अवरूद्ध कर दिये जाने पर जैसे समूचा राज्य ठहर गया।

सी पी आइ (एम) के तीन बार विधायक रहे किसान सभा के अध्यक्ष अमराराम व पूर्व विधायक तथा किसान सभा के नेता पेमाराम के नेतृत्व में हुए आंदोलन का सीकर मुख्य केंद्र रहा। ट्रेड यूनियनों व छात्रों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, व्यापारियों व अन्यों के द्वारा एकजुटता के अभूतपूर्व प्रदर्शन ने इसे एक जन आंदोलन बना दिया। महिलाओं की भागेदारी महत्वपूर्ण थी और कई जगहों पर इसने अहम भूमिका अदा की। कई विपक्षी पार्टियों ने भी आंदोलन का समर्थन किया और उनके नेताओं ने किसानों की सभाओं को संबोधित किया। लोगों ने भोजन व अन्य चीजों की आपूर्ति कर व वित्तीय सहयोग देकर आन्दोलनरत किसानों की मदद की। भटठा मजदूर यूनियन तथा बस व आटों चालकों की यूनियनें ट्रकों, बसों व ऑटो के साथ जुलूसों में शामिल हुईं।

जिला प्रशासकों के घरों के सामने 'जागो' रैली निकाली गयी। बड़ी संख्या में किसानों व महिलाओं की जोशीली भागेदारी के साथ वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की अंत्येष्टि की गयी।

अंततः, राजे सरकार के मंत्री समूह ने अमराराम व पेमाराम के नेतृत्व वाले किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल से घंटो लंबी बातचीत की जो 12 सितम्बर को दोपहर में शुरू होकर 14 सितम्बर की सुबह तक चली। तब जाकर राजस्थान किसान सभा ने आंदोलन वापस किया और राज्यभर में विजय का उत्सव मनाया गया।

समझौते में, सरकार 50,000 रूपये तक की कर्ज माफी के लिए सहमत हुई जिससे 8 लाख किसानों को लाभ मिलेगा; स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुरूप कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर और मूंगफली, मूंग व उड़द को जिला मुख्यालयों पर 7 दिन के अन्दर खरीदने, तथा समय सीमा के भीतर न्यूनतम समर्थन मूल्य के क्रियान्वयन के तरीके के बारे में केन्द्र सरकार को लिखने; ड्रिप सिंचाई के लिए बिजली की दरों में की गयी बढ़ोतरी को वापस लेने; बकायों के साथ एस सी/एस टी/ओ बी सी फेलोशिप के तुरन्त भुगतान; पशु बिक्री पर लगी पाबंदियों में ढ़ील देने; आवारा पशुओं व जंगली जानवरों से फसलों के बचाव; बुजुर्ग किसानों को 2000 रूपये वृद्धावस्था पेंशन; नहर सिंचाई विफल रहने पर बीमा दावा तथा पुलिस द्वारा किसानों व व्यपारियों के उत्पीड़न को रोकने पर सरकार सहमत हुई।

15 सितमबर को, सीटू ने किसान सभा व किसानों को सफल आंदोलन व उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए बयान जारी किया; सीटू ने आंदोलन का समर्थन करने के लिए मजदूरों, ट्रेड यूनियनों व जनता के अन्य तबकों को भी बधाई दी। यह आंदोलन देश भर में मजदूर आंदोलन के लिए एक बड़ी प्ररेणा है। सीटू ने मजदूरों से इस आंदोलन से सीखने तथा 9–11 नवम्बर के दिल्ली में होने वाले महापड़ाव को शानदार रूप से सफल बनाने का आहवान किया है।

बंगलुरु में मजदूरों का ऐतिहासिक मार्च

कर्नाटक में यह अभी तक की मजदूरों की या अन्य किसी भी वर्गीय व जन रैलियों में सबसे बड़ी रैली थी। सीटू की कर्नाटक राज्य समिति के बैनर तले में आंगनवाडी, आशा, मिड–डे मील; पंचायत मजदूरों, नगरपालिका मजदूरों, निर्माण, बीड़ी; बोझा उठाने वालो; सरकार में, बिजली में, बी एस एन एल के ठेका मजदूरों; तथा निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के मजदूरों की सीटू की 178 यूनियनों के 40,000 मजदूर कर्नाटक के 30 जिलों से 14 सितम्बर को '' नम्मानाडे– *बेंगालुरिनेडे महानाडे'' (बंगलुरू की ओर विशाल मार्च)* के शंखनाद के साथ सैलाब के रूप में बंगलुरू में उमड़ पड़े। मार्च का जुलूस मजदूरों की मांगों को आगे बढ़ाकर उठाने के लिए संगोली रेलवे स्टेशन से विधान सभा की ओर चला। मांगों में 18,000 रूपये न्यूनतम वेतन, ठेका प्रथा के खात्मे, समान काम के लिए समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में सीटू को शामिल करने तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की तरह ही त्रिपक्षीय कर्नाटक श्रम सम्मेलन का गठन कर उसका सत्र बुलाने; तथा बी ई एम एल सहित निजीकरण करने के केन्द्र सरकार के कदम का विरोध करने की मांगें शामिल थी।

फ्रीडम पार्क के पास पहुँचने पर मार्च के जुलूस ने शेषाद्री रोड पर कब्जा कर लिया और अनिश्चित कालीन धरना दे दिया। शहर के मुख्य मार्ग अवरूद्ध हो गये। आंदोलनकारी मजदूरों के इस रैली–धरने को सीटू की राज्य अध्यक्ष वरालक्ष्मी, महासचिव मीनाक्षी सुंदरम व सी पी आइ (एम) के राज्य सचिव जी वी श्रीराम रेड्डी ने संबोधित किया। राज्य के श्रम मंत्री ने दोपहर बाद रैली धरना स्थल पर आकर मजदूरों की रैली की मांगों के बारे में सरकार के निर्णयों की घोषणा की। सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में सीटू को शामिल करने की अधिसूचना जारी की तथा कर्नाटक श्रम सम्मेलन आहूत करने पर सहमति ही। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि पूर्व में दिये गये आश्वासनों को लागू करने के लिए कुछ लंबित पड़े कानूनों को जल्द पारित किया जायेगा। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के व मिड–डे–मील वर्करों के कुछ विशेष मुद्दों का भी समाधान निकाला गया।

इस मार्च की तैयारी के लिए राज्य स्तरीय कार्यशालायें की गयीं व जत्थे निकाले गये। 29 जुलाई से 13 अगस्त तक विदुरास्वथ से कंडापुरा तक निकला राज्य स्तरीय जत्था लाखों लोगों तक पहुँचा। *(सीटू मजदूरः सितम्बर, 2017)* । इसने मांगों को लोकप्रिय बनाया और सरकार व मालिकों के झूठों को बेनकाब किया।

बैंक हड़ताल व रैली

देश भर में वित्तीय सेवायें प्रभावित हुईं; सुधारों के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध''

22 अगस्त की शाम तक मीडिया ऐसा कहते हुए बता रहा था, ''अन्य मुद्दों के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का विरोध करते हुए समूचे देश में 1,30,000 से ज्यादा शाखाओं में 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारियों द्वारा काम बंद रखने के चलते मंगलवार को सारे देश में बैंकों का काम–काज प्रभावित हुआ–जिससे चेक क्लियरेंस कार्य भी प्रभावित रहा''।

15 सूत्रीय मांगपत्र में निजीकरण करने और पी एस यू बैंकों का विलय करने के कदम के विरोध को सबसे पहले रखते हुए; बैंकिग उद्योग के कर्मचारियों व अधिकारियों की 9 यूनियनों के संयुक्त मंच–यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यू एफ बी यू) के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको, निजी क्षेत्र व विदेशी बैंको समेत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको व कुछ राज्यों में सहकारी बैंकों के कर्मचारी 22 अगस्त को सुबह से शाम तक देशव्यापी हड़ताली पर रहे। हड़ताल से देशभर में बैकिग काम–काज व लेन–देन पूरी तरह ठप्प रहा। नबार्ड व रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने, हड़ताली कर्मचारियों के साथ एकजुटता में प्रदशन किये।

यह हड़ताल केंद्र की सरकार के पब्लिक सैक्टर बैकों के विलय व कोंसोलिडेशन के कदम के खिलाफ, सेवा शुल्कों में वृद्धि व जमाओं पर ब्याज घटाकर जानबूझकर बैंकों का ऋण अदा न करने वालों के बोझ को उपभोक्ताओं पर डालने, जी एस टी के मद में सेवा शुल्कों में वृद्धि, बैकों का पैसा न लौटाने वालों को लोन रीस्ट्रक्चरिंग, असेट्स रीकन्सट्रक्शन, बट्टे खाते व माफी आदि के माध्यम से बचाये व बनाये रखने के कदमों के खिलाफ तथा फंसे कर्ज की वसूली के लिए कड़े कानूनी व प्रशासनिक कदमों की मांग, जान बूझकर पैसा मार लेने को ''आपराधिक कृत्य'' घोषित करने इसके लिए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई, बुरे कर्जो की वसूली के बारे में संसद की समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन, बुरे कर्ज को पैदा करने के लिए शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय किये जाने, बैंक बोर्ड ब्यूरों की समाप्ति, तथा एफ आर डी आई विधेयक को वापस लिए जाने आदि की मांगों को लेकर की गयी थी।

दिल्ली में रैली: आंदोलन के अगले चरण में यू बी एफ यू ने निजीकरण व जन विरोधी कारपोरेट हितैषी बैंक सुधारों के खिलाफ 15 सितम्बर को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय विरोध रैली आयोजित की। यू एफ बी यू के घटकों के नेताओं की अगुआई में जुलूस रामलीला मैदान से संसद भवन भवन की ओर रवाना हुआ।

जब जुलूस का शुरूआती हिस्सा संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने पहुँचा तब उसका आखिरी छोर राम लीला मैदान से बाहर नहीं निकला था, जुलूस सारे क्नाट प्लेस क्षेत्र में फैला था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण व विलय के कदम के खिलाफ तथा जानबूझकर कर्ज वापस न करने वालों के विरूद्ध आपराधिक मामले शुरू करने व कर्ज वसूली के लिए उनकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग करते हुए नारे बुलंद किये गये।

संसद मार्ग पर प्रदर्शन व जुलूस एक रैली में बदल गया और समूची जगह पूरी तरह भर गयी। विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं– सी पी आइ (एम) महासचिव व सांसद सीताराम येचुरी, सी पी आइ के सांसद डी. राजा, काँग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, जे डी (यू) सांसद शरद यादव, शिव सेना सांसद अरविन्द सावंत ने रैली को सम्बोधित करते हुए बैंक कर्मियों के संधर्ष को अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया। रैली को सम्बोधित करने वाले केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं में सीटू महासचिव व सांसद तपन सेन, एटक नेता अमरजीत कौर तथा इंटक, यू टी यू सी, व ए आइ यू टी यू सी के नेता शामिल थे। कॉमरेड डी. राजा के नेतृत्व में यू एफ बी यू में शामिल बैंक यूनियनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्तमंत्री अरूण जेटली से मुलाकात कर उन मुद्दों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जिन्हें लेकर बैंक यूनियनें आन्दोलनरत हैं। यू एफ बी यू आगामी अक्टूबर/नवम्बर में दो दिन की हड़ताल करेगा।

दलित व शहरी, ग्रामीण स्थानीय निकायों के मजदूर

19 सितम्बर को, सीटू के केद्रीय सचिव मंडल के सदस्यों के अलावा 10 राज्यों के 38 प्रतिनिधियों ने, सीटू की वर्किंग कमेटी के निर्णय के अनुसार दलित मजदूरों के सामने आने वाले खास मुद्दों पर बुलायी गयी बैठक में भाग लिया। बैठक दिल्ली में बी टी आर भवन में हुई। अध्यक्ष हेमलता ने बैठक का मकसद स्पष्ट किया और महासचिन तपन सेन ने शुरूआती व भूमिका संबंधी टिप्पणिंया कीं। 17

प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लेते हुए पहलकदमी का स्वागत किया और दलित मजदूरों द्वारा कार्य स्थलों पर किये जाने वाले कई तरह के भेदभावों को सामने रखा।

चर्चा का समापन करते हुए तपन सेन ने सरकार की विभाजनकारी रणनीति; कार्य स्थलों पर सामने आने वाले भदेभावों के बारे में दलित मजदूरों के अनुभवों; जमीनी स्तर पर सीटू यूनियनों द्वारा तुरन्त हस्तक्षेप करने को जरूरत; तथा वर्गीय एकता व वर्ग संधर्ष मुद्दों को ट्रेड यूनियन मंच से उठाने के महत्व की स्पष्ट किया। 20 सितम्बर को 10 राज्यों से पंचायतों व त्रिस्तरीय शहरी निकायों के म्यूनिसिपल मजदूरों के 44 प्रतिनिधि बी टी आर भवन में हुई बैठक में शामिल हुए। तपन सेन व हेमलता द्वारा शुरू की गयी चर्चा में 19 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने स्थानीय निकायों के मजदूरों के हालात, उनके काम की स्थिति पर नवउदारवादी नीतियों के असर, अपने संधर्ष, सरकार के रवैये व अपनी यूनियनों की सांगठनिक स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने सीटू की पहल का स्वागत किया और समय–समय पर ऐसी बैठक करने में स्थानीय नियमों के काम के ठेकाकरण व आऊटसोर्सिंग के बारे में; कई राज्यों में सरकारी आदेशों का क्रियान्वयन न किये जाने तथा कार्य स्थलों पर सुरक्षा की अनुपस्थिति में कितने ही म्यूनिसिपल मजदूरों की मौतों व स्वास्थ्य को हाने वाले नुकसान के बारे में बताया।

सीटू सचिव मंडल इन बैठकों में आये सुझावों व निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय पर निर्णय लेगा।

आंध्रप्रदेश के स्थानीय निकायों के संधर्षरत मजदूर

सीटू की ए पी ग्राम पंचायत एम्पलाईज वर्कर्स यूनियन ने वेतन वृद्धि की माँग करते हुए ''चलो विजयवाड़ा'' के आहवान के तहत जिलों में कलेक्टरों के कार्यालयों के समक्ष धरने दिये।

राज्य में शहरी नगरपालिकाओं में 40,000 ठेका व आऊटसोर्स मजदूर हैं और 10,000 स्थायी मजदूर हैं। सीटू की म्यूनिसिपल वर्कर्स एम्पलाईज फेडरेशन, नगर पालिकाओं को काम की आऊटसोर्सिंग करने की मंजूरी देने वाले सरकारी आदेश सं० 279 के खिलाफ पिछले 19 महीनों से संधर्ष में हैं जिसमें 4 बार ''चलो विजयवाड़ा'' अभियान शामिल है; लाखों परचे बांटे गये हैं और हजारों पोस्टर लगाये गये। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फेडरेशन के महासचिव व कार्यकारी अध्यक्ष को निशाना बनाते हुए घायल किया। नेल्लोर में 50 से ज्यादा मजदूर पुलिस ने लाठी चार्ज में घायल हुए और उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया गया। सीटू की भागेदारी वाली संयुक्त कार्रवाई समिति (जे ए सी) द्वारा किये 3 दिन की हड़ताल के आहवान पर 11–13 जुलाई, 2017 की हड़ताल में 30,000 ज्यादा मजदूर शामिल हुए, 22000 मजदूर धरनों व आंदोलनों में शामिल हुए। विजयवाड़ा में सत्तारूढ पार्टी के नेताओं ने मजदूरों को जी ओ 279 के पक्ष में लामबंद करने का प्रयास किया। श्रीकाकुलम में बी एम एस यूनियन ने जी ओ 279 के पक्ष में परचे छपवाये और मजदूरों के मनोबल व हड़ताल को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे और हड़ताल पूरी तरह से सफल रही। परिणामस्वरूप, 12 जुलाई को मंत्री समूह ने यूनियनें से वार्ता की और ''काम को आऊटसोर्स करने के लिए टैंडरों को कुछ समय के लिए रोक दिया। सीटू यूनियनें रोजगार की सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन, नियमित किये जाने तथा कुशल व अर्धकुशल मजदूरों के लिए अलग–अलग वेतन की मांगों को लेकर भी कई सारे आंदोलन कर रही हैं। सीटू यूनियनों ने 15 सितम्बर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है। जे ए सी ने भी हड़ताल का नोटिस देने की धमकी दी है। सरकार ने 13 सितम्बर को जे ए सी के साथ वार्ता की। सीटू यूनियनों ने 'काम की आऊटसोर्सिंग' के टेंडरों को रोकने की मांग की है। 22 सितम्बर को अगले चरण की वार्ता होगी।

कोलकाता में नगरपालिका मजदूरों की संयुक्त रैली

6 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आहवान पर, पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा नगरपालिका मजदूर अपने 11 सूत्री मांगपत्र को लेकर 11 अगस्त को कोलकाता के रानी राशमणि रोड स्थित, कोलकाता म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मुख्यालय के सामने हुई रैली में शामिल हुए। रैली व जन सभा को सीटू के राज्य अध्यक्ष सुभाष मुखर्जी, पश्चिम बंगाल नगरपालिका मजदूरों की संयुक्त आंदोलन समीति के संयोजक दीपक मित्रा तथा तपन मुखर्जी, सुरंजन भट्टाचार्जी, अमिताव भट्टाचार्जी व मानस सिन्हा समेत अन्य यूनियन नेताओं ने संबोधित किया। रैली की अध्यक्षता रतन भाट्टाचार्य ने की। बैठक को संबोधित करते हुए दीपक मित्रा ने कहा तृणमूल काँग्रेस सरकार के मजदूर विरोधी रवैये की चर्चा की। कई बार लिखित में देने के बावजूद नगरपालिका मामलों के व वित्त के मंत्रियों ने मजदूरों

की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नही दी। नगरपालिका मंत्री ने तो मांगो का ज्ञापन लेने से ही मना कर दिया। तृणमूल नेतृत्व वाला स्थानीय निकाय प्रशासन मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रहा है। रैली के बाद मजदूरों की 11 सूत्री माँगों का ज्ञापन सरकार को भेजा गया। इसमें कैजुअल मजदूरों के रोजगार को नियमित किये जाने; कैजुअल मजदूरों को दिये जाने लाभों क

` बारे में वित्त विभाग के सर्कुलर को लागू किये जाने; समान काम, समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने; श्रम कानूनों की पालना कराने; महँगाई भत्ते के 34 प्रतिशत बकाये के तुरन्त भुगतान; बिना देरी के 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें घोषित करने; कार्य के दौरान मृत्यु पर मिलने वाले लाभ को रोकने के आदेश को वापस लिये जाने; परेशान करने के लिए होने वाले स्थानान्तरण, उत्पीडन को रोकने; तथा अन्य मांगों के साथ मजदूरों को पूरे ट्रेड यूनियन अधिकार दिये जाने की माँगे शामिल थी। रैली में टी एम सी सरकार के मजदूर विरोधी रवैये की निन्दा की गयी। यह फैसला किया गया कि पालिका मजदूर नगरपालिकाओं, जिलों व राज्य स्तर पर संयुक्त रूप से आन्दोलन करेंगे।

राज्यों से *पृष्ठ 18 से आगे,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*

असम

ट्रेड यूनियनों द्वारा बाढ़ राहत

सीटू व ज्वायंट कौंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन (जे सी टी यू) की एक 24 सदस्यीय टीम ने 24 सितम्बर, 2017 को असम के साभोग क्षेत्र के कलपानी इलाके के बाढ से बुरी तरह प्रभावित गांवों का दौरा किया। टीम ने बाढ राहत कार्य के रूप में, बाढ के कारण बेघर हो गये 50 परिवारों को टिन की चादरे दान की ताकि उन्हें सिर छिपाने के लिए इंतजाम करने में मदद हो सके।

राज्यों से

बिहार

सफाई मजदूरों की सेवा नियमित करने के लिये धरना

सफाई मजदूरों की सेवा नियमित करने की मांग पर सफाई मजदूर यूनियन, बिहार की ओर से 19 सितम्बर को पटना में मूख्य मंत्री के समक्ष आक्रोशूर्ण प्रदर्षन एवं रैली व धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता अनुप राम ने की। रैली में पटना, जमुई,, भागलपुर में तथा अन्य जिलों के सफाई मजदूरो ने बड़ी संख्य भाग लिया। रैली को सी.आई.टी.यू. के,अरुण कुमार मिश्र, कर्मचारी महासंघ के नेता मंजुल कुमार दास, शशिकान्त राय, राज किशोर राय, यूनियन के महासचिव शंकर साह, कोशाध्यक्ष महेश्वरी प्रसाद, नालन्दा मेडिकल कॉलेज के रघुनाथ पासवान, और राधिका देवी, जमुई के पिंकु हरिजन अशोक कुमार और विक्की डोम, हवाई अड्डा पटना के विजय राम और बबलू कुमार, मसौढ़ी के विन्दा डोम, राजा कुमार अम्बेदकर और राजु डोम भागलपुर के संजय हरि अम्बेदकर ने सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि सफाई मजदूरों की दुर्दषा के मूलतः आर्थिक और सामाजिक कारण तो हैं ही, इसके लिये सरकार भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। आर्थ्रिक सामाजिक और षैक्षिणिक रूप से सबसे वंचित दलित जाति/वर्ग, मानसिक पीड़ा को झेलते हुए सफाई का काम करते आ रहे हैं। सफाई के काम को समाज में घष्णा का काम समझा जाता है और इस काम को करने वालों को अछूत समझा जाता है और कहा भी जाता है।

गाँव, कस्बा,शहर नगर और महानगर को साफ करने वाला सफाई मजदूर गंदगी के बीच झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इनकी बस्तियों में आग लगना या लगाया जाना आम बात है। अवैध कब्जा के नाम पर इनकी बस्तियों को समय समय पर उजाड़ने का काम किया जाता है। सरकारें इनके लिये आवासीय जबावदेही से अपने आप को मुक्त समझती है। इन्दिरा आवास,बी.पी.एल.वृद्धा पेंशन,विधवा पेंशन,विकलांग पेंशन जैसे सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी सफाई मजदूर आम तौर पर वंचित ही हैं। अनिवार्य रूप से स्थाई काम काम करने वाले सफाई मजदूरों को ठेका पर रख कर काम कराया जाता है। ठेका (उन्मूलन एवं नियमन) अधिनियम–1970 का लाभ सफाई मजदूरों को नहीं मिलता है। सफाई मजदूरों का चौतरफा शोषण जारी है।

.बिहार सरकार के संस्थानों, कार्यालयों,अस्पतालों, निगम, बोर्ड आदि में काम करने वाले सफाई मजदूरों को 100/– रुपये के आस–पास मजदूरी दी जाती है। अधिकांष मामलों में खातों के माध्यम से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। मनमानी छंटनी वह हथियार है जिसके कारण मजदूरों का चौतरफा शोषण जारी है। जीविका का दूसरा कोई वैकल्पिक उपाय के अभाव में दलित जाति/वर्ग के लोग गंदे नालों की सफाई मरे और सड़े गले जानवरों का निस्तार करने के लिये बाध्य हैं।

कचरा फेकने का स्थान निर्धारित नहीं होनेके कारण भी सफाई मजदूरों को ही आम लोगों का कोपभाजन होना पड़ता है। इसलिये कचरा फेकने का स्थान का निर्धारण एवं उसके निस्तारण का उपाय भी जरूरी है।

सफाई मजदूरों की जीविका और जिन्दगी में बदलाव के लिये यूनियन ने मुख्य मंत्री से ठेका प्रथा की समाप्ति, सभी सफाई मजदूरों का नियमितिकरण और देश भर में सफाई मजदूरों के लिये एक समान वेतन, 18000/–रुपये न्यूनतम वेतन और सफाई मजदूरों के लिये ग्रेड युक्त कैडर का निर्माण परिचय पत्र निर्गत करना, छंटनी पर रोक लगाना, समय पर वेतन का भुगतान तथा बैंक खाते के माध्यम से वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना, ई.पी.एफ., ई.एस.आई., ग्रेचुटी., बोनस एवं पेंषन लाभ देना, वर्दी, मास्क, दस्ताना, अन्य सुरक्षात्मक जरूरी उपकरण एवं आधुनिक औजार की आपूर्त्ति नाले, टंकी एवं सीवर में प्रवेश पर रोक, काम के दौरान मृत्यु पर दस लाख रुपये और सामान्य मृत्यु पर पाँच लाख का पारिवारिक अनुदान एवं एक आश्रित को नियमित सेवा में बहाली साथ ही स्वास्थ्य कारणों से सेवामुक्ति के आधार पर भी आश्रित की नियुक्ति, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों मे सफाई मजदूरों के बच्चों कों मुफ्त शिक्षा नियमित रुप से च्यापक स्वास्थ्य जाँच एवं परिवार सहित मुफ्त इलाज सफाई काम में मुंशी, मेठ और सुपरवाईजर के पद पर प्रोन्नति., बेघर सफाई मजदूरों को शौचालय युक्त आवास उपलब्ध करना, सभी को बी.पी.एल. सूची में शामिल करना, कचरे को फेंकने का स्थान का निर्धारण तथा उसके रूपांन्तरण के उपाय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुशंसाओं को लागू करना और राज्य सफाई आयोग का गठन किये जाने की मांग की। *(योगदानः शंकर साह)*

निमार्ण कामगार यूनियन का सम्मेलन

निमार्ण कामगार यूनियन (सीटू) का दूसरा राज्य सम्मेलन 10 सितम्बर, 2017 को मुजफ्परपुर में आयोजित किया गया। प्रतिनिधि सत्र की शुरूआत में जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा– विकल्प की और प्रतिकल्प की ओर से जनवादी गीतों व नाटक का मंचन किया गया। सत्र को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव भैरव सिंह शेखावत ने मजदूरों को याद दिलाया कि राजनीतिक दल किस प्रकार झुठे वादे कर सरकार में आ जाते हैं और मजदूरों के खिलाफ व पूंजीपतियों के हित में काम करते हैं। प्रतिनिधि सत्र को यूनियन के पंजाब के नेता गंगा प्रसाद व सीटू के बिहार राज्य महासचिव तथा सम्मेलन के पर्यवेक्षक गणेश शंकर सिंह ने भी संबोधित किया और कहा कि संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय है। विकास का दंभ भरने वाली सरकारें कारखाने लगाने के बजाय उन्हें बंद कर रहीं हैं। प्रतिनिधि सत्र पेश रिपोर्ट पर निर्माण मजदूरों ने अपनी बात रखते हुए समस्याओं को उठाया और यूनियन को मजबूत करने की आवश्यकता बतायी।

सम्मेलन में 35 सदस्यीय नई राज्य कमेटी का गठन हुआ जिसमें सुंदेश्वर सहनी को अध्यक्ष नाथुन तमादार को महामंत्री, अनिल यादव भुवनेश्वर प्रसाद, वीर बहादुर राज्य को उपाध्यक्ष, शम्भु यादव, रमधीर प्रसाद, अहमदअली को संयुक्त मंत्री तथा उमेश कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन ने प्रस्ताव पारित करो मजदूरों की मांग पर 9–11 नवम्बर के ट्रेड यूनियनों के अखिल भरतीय आंदोलन में भाग लेने, बालू के सवाल पर 27 सितमबर को जिलों में धरना व 19 सितम्बर को बिहार विधान सभा पर प्रदर्शन का भी निर्णय लिया।

उत्तराखण्ड

भोजन माताओं का सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन

सीटू से सम्बद्ध उत्तराखण्ड भोजन माता कामगार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 14 सितम्बर 2017 को देहरादून के लोकल बस स्टैंड स्थित सीटू कार्यालय पर एकत्रित होकर सचिवालय कूच किया, जो इंद्रा मार्केट, लेन्सडॉन चौक से होते हुये कनक चोक पर पुलिस दुवारा बैरिकेड लगा कर जलूस को रोक दिया इस दौरान भोजन मातायें वहीं धरना दे कर बैठ गई और सभा की।

सीटू के जिला सचिव लेखराज ने सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि उत्तराखंड सरकार मध्याह्न भोजन योजना को निजी हाथो में दे रही है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश कि ताजा पका हुआ भोजन ही बच्चो को दिया जाये, उलंघन कर रही है। संसदीय कमेटी द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है किन्तु यह सरकार मध्याह्न भोजन योजना का निजीकरण करने पर उतारू है।

सभा को सीटू के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र भंडारी ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथो लेते हुये कहा कि मोदी सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के बजट में भारी कटौती की है। सरकार की मंशा इसे बंद करने की है। उन्होंने कहा की राज्य सरकार द्वारा भोजन माताओं को हटाने की साजिश कतई बर्दास्त नही किया जायेगा।

यूनियन की महामंत्री मोनिका ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री उन्हें वार्ता के लिए नही बुलाते हैं तो भोजनमाताये बड़ा आन्दोलन करेंगी।

ज्ञापन में भोजनामाताओं से अतिरिक्त कार्य न कराया जाये, स्वास्थ्य बिमा कराया जाये, न्यूनतम वेतन देने निकाली गई भोजनमाताओं को वापस कार्य पर रखने, कार्य से निकालना बंद करने एवम सामाजिक सुरक्षा देने आदि मांगें थी। *(योगदान : मोनिका)*

समझौते के बाद बाद चालक-संवाहको ने रोकी हड़ताल

प्रशासन द्वारा मांगों पर सुनवाई न किये जाने पर सीटू से संबंद्ध देहरादून जिला चालक संवाहक यूनियन ने 21 अगस्त से अनिश्चित कालीन हड़ताल का नोटिस दिया। तथापि 20 अगस्त को ह बसमालिकों की एसोशिएसन यूनियन के बीच चर्चा व चालकों का वेतन 400 रूपये व संवाहकों का 200 रूपये बढ़ाने के समझौते के बाद यूनियन ने हड़ताल रोक दी।वार्ता में यूनियन के अध्यक्ष प्रमोद सिंह, महासचिव नवीन कुमार, कोषाध्यक्ष मासूम अली तथा सीटू के जिला अध्यक्ष लेखराज शामिल थे।

दिल्ली –एन सी आर

दुकान कर्मचारी यूनियन का सम्मेलन

दिल्ली दुकान कर्मचारी यूनियन का सातवाँ सम्मेलन 10 सितम्बर, 2017 को श्रद्धानन्द मार्केट में हुआ। सीटू दिल्ली राज्य कमेटी के प्रधान विरेन्द्र गौड़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया एंव उपप्रधान हरीश चन्द पन्त ने सम्बोधित किया। समापन भाषण सीटू दिल्ली राज्य कमेटी के सचिवमंडल सदस्य कुशवाहा ने दिया। सभी वक्ताओं ने यूनियन के कार्यों की सराहना करते हुए, सदस्यता बढ़ाने एंव सगंठन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मेलन में सीटू दिल्ली कमेटी रेहड़ी पटरी खोमचा हाकर्स यूनियन के महासचिव जगदीश मनोचा चन्द, एडवोकेट अब्राहम, जनवादी महिला समिति की ताजदार सुल्तान एंव नसीमा, सोशल वेलफेयर समिति की नजमा एंव फातिमा और ट्रान्सपोर्ट यूनियन के महासचिव शैतान सिंह उपस्थित थे। सम्मेलन में 140 डेलीगेटों ने हिस्सा लिया और यूनियन सदस्यों के हितो को देखते हुए सर्वसम्मति से मांग पत्र पर प्रस्ताव पास किया जिसमें न्यूनतम वेतन दुकानों पर कार्य करने वाले ठेला रिक्शा, पल्लेदारो का बीमा, भविष्य निधि, और मेडिकल की सुविधा और ई. एस. आई., साप्ताहिक छुट्टियों के अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टियां, वार्षिक छुट्टियों के दिन काम करने पर ओवर टाइम, नगों के हिसाब से काम करने वालों के पैसों की बढोतरी, बोनस दिया जाय, न्यूनतम वेतन 18000 किये जाने, की मांगे शामिल थीं। अब्दुल सत्तार को यूनियन का प्रधान व गोकुल प्रसाद यादव को महासचिव चुना गया। *(योगदान : अब्दुल सत्तार)*

सुपरवाइजरी स्टाफ की नौकरी पर पैदा खतरे के खिलाफ रोष प्रदर्षन

दिल्ली महिला बाल विकास विभाग में ठेका/आउटसोर्स पर कार्यरत सैकड़ों की संख्या में सुपरवाइजरी स्टाफ की नौकरी व आजीविका पर विभाग के अधिकारियों की कर्मचारी विरोधी नीति व रवैये के कारण खतरा पैदा हो गया है। ये कर्मचारी दिल्ली की महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के महत्वपूर्ण कार्य में दिन रात लगी रहती हैं। इन्हें न तो स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन व अन्य सेवा शर्त्ते दी जाती हैं और न ही अन्य कोई सुविधा प्राप्त है। ये इस विभाग में पिछले कई वर्षो से कार्यरत हैं। इन्हें सदैव नौकरी से निकाल बाहर कर देने की धमकी दे दी जाती है। इनके विषय में दिल्ली सरकार का यह विभाग ठेका नियमन व उन्मूलन कानून 1970 व अन्य कानूनों का घोर उल्लंघन कर रहा है। देश के सर्वेच्च न्यायालय द्वारा दिये आदेशों की भी अनुपालना नहीं की जा रही और इन्हें ठेका/ आउटसोर्स कर्मचारियों की तरह मानकर स्थायी कर्मियों से कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है। अब विभाग ने इन पर नये सिरे से कुठाराघात करते हुए 2015–2016 में भर्ती किये गये सुपरवाइजरी स्टाफ को नौकरी से बाहर करने का निर्णय ले लिया है और इनके स्थान पर दूसरे नये स्टाफ की भर्त्ती की गयी है। यह अन्यायपूर्ण है क्योंकि नियमानुसार स्थायी रिक्तियों को भरने हेतु विभाग में ठेका/आउटसोर्स कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो कि विभाग द्वारा नहीं दी गयी।इन्हें नियुक्ति हेतु ली गई परीक्षा में बैठने की भी अनुमति नहीं दी गयी।

दिल्ली महिला बाल विकास विभाग के इस अन्यायपूर्ण कदम के खिलाफ सीटू से सम्बद्ध दिल्ली आफिसिज एंड इस्टेबिलिस्मेंट इम्पलाईज यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल सीटू राज्य महा सचिव श्री अनुराग सक्सेना के नेतृत्व में विभाग की निदेशिका श्रीमति शिल्पा शिंदे से मिला और उन्हें एक पत्र भेंट कर अनुरोध किया कि ठेका/आउटसोर्सिग पर वर्षो से कार्यरत किसी भी सुपरवाइजरी स्टाफ को नौकरी से न निकाला जाये क्योंकि ऐसा करने से उनकी आजीविका गम्भीर खतरे में आ जायेगी तथा परिवार भूखमरी का शिकार हो जायेगा। निदेशिका महोदया से प्रतिनिधि मंडल ने यह अनुरोध भी किया कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती न की

जाये। प्रतिनिधि मंडल में सीटू व यूनियन के नेता अनुराग सक्सैना, एस.सी.पंत, लक्ष्मी नारायण, कमला, विक्रम, निशा, मोनिका, शशी, सुनीता आदि सम्मिलित थे।

दिल्ली सरकार की महिला बाल विकास विभाग की निदेशिका श्रीमति शिल्पा शिंदे का सीटू प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करने का ढंग अनुचित व दुर्भाग्यपूर्ण व निराशापूर्ण था। उन्होंने कर्मचारियों की गम्भीर व ज्वलंत समस्या का निदान करने के बजाय इनके प्रति एकदम नकारात्मक व दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया अपनाया जिससे महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत सुपरवाइजरी स्टाफ एवं यूनियन प्रतिनिधि मंडल में रोष व्याप्त हो गया।

दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली पर स्थित महिला बाल विकास विभाग के मुख्यालय के द्वार पर एकत्रित सैकड़ों महिला सुपरवाइजरों ने विभाग की निदेशिका के दोष पूर्ण व्यवहार के खिलाफ सीटू दिल्ली राज्य कमेटी के नेतष्त्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों साथियों को सीटू दिल्ली राज्य के महासचिव श्री अनुराग सक्सैना, उपाध्यक्ष श्री एच.सी.पंत, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण व कामगार महिला नेता कमला ने सम्बोधित किया। सभी वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि महिला बाल विकास विभाग से अधिकारियों ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए तथा नकारात्मक रवैया अपनाते हुए सुपरवाइजरी स्टाफ या किसी भी ठेका/आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया तो यूनियन को गम्भीर संगठनात्मक कदम उठाने को बाध्य होना पड़ेगा जिसमें लगातार धरना, प्रदर्शन, रैली व हड़ताल आदि शमिल होंगे। *(योगदानः लक्ष्मी नारायण)*

न्यूनतम वेतन व श्रम कानून लागू कराने की मांग पर धरना व प्रदर्शन

uk,Mk] e elll ykm.M cd d çcU/kdk }kjk yxkrkj Je dkuuk dk mYy?ku dj dekpkfj;k dk vkfFkd o ekufld :i l 'kk"k.k djus d f[kykQ 13 flrEcj dk oL= flykb m|kx dkexkj ;fu;u lhV d urRo e etnjk u dEiuh d lkeus /kjuk@çn'ku fd;k vkj Je o dkj[kkuk dkuuk dk ykx djus dh ekx dh dekpkfj;k dk lEckf/kr djr g, lhV ftyk/;{k xx'oj nÙk 'kek u crk;k fd cd lLFkku dk pyr 10 o"k l Hkh vf/kd le; gk x;k yfdu vkt rd Hkh dkj[kkus e Je dkuu ykx ugh gA çcU/kd lLFkku e 12 ?kV dh nk f'k¶Vk e dk; djkr g vkj dk;jr Jfedk dk Je dkj[kkuk dkuuk d rgr feyus okyh fof/kd Je lfo/kk, o çn'k ljdkj }kjk ?kkf"kr U;ure oru rd ugh nr g rFkk vkojVkbe dk Hkh dkuuu Hkxrku ugh djr gA bruk gh ugh Jfedk dk ckul Hkh ugh fn;k tkrk g vkj ifjp; i= fu;fä i= vkfn Hkh ugh fn; tkr g tk Jfedk d lkFk ?kkj vU;k; gA lhV ftyk egklfpo jkelkxj us dgk fd ;fn çcU/kdk u le; jgr dekpkfj;k dh ekx ugh ekuh rk lhV cMk vkUnkyu djxk ftldh lEi.k tckongh çcU/kdk dh gkxh] lhV ftyk lfpo jkeLokjFk us ljdkj dh etnj fojk/kh uhfr;k dh ppk dh vkj 09&10&11 uoEcj 2017] d lln ij gkus okyr egkiMko e Hkkjh l[;k e 'kkfey gkus dh vihy dhA fojk/k lHkk dk dekpkjh urk no ukjk;.k] txnh'k] vuri] vuoj vyh] ljr'k] ujr'k vkfn us Hkh lEckf/kr fd;kA

हरियाणा

किसान-मजदूर रैली की तैयारी

lhvkbVh;] 3 väcj dk fglkj e gkus okyh fo'kky fdlku&etnj jyh d fy, çn'k d yk[kk etnj&fdlkuk d chp vfHk;ku pyk jgh gA tk,xhA VM ;fu;uk d vk°oku ij 9 l 11 uocj dk fnYyh

e gku oky etnjk d egkiMko e Hkh çn'k l cMh ykecnh dh tk,xhA mä Qlyk lhV gfj;k.kk dh jkT; Lrjh; vke lHkk e fy;k x;kA lHkk dh v/;{krk jkT; v/;{k lrchj flg u dhA ble jkT; d 21 ftyk l 200 l T;knk dk;drkvk u fgLlk fy;kA

lHkk dk lckf/kr djr g, lhV dh jk"Vh; lfpo ,-vkj-flU/k u dgk fd Hkktik dh dUæ ljdkj cM dkjikjV ?kjkuk d i{k e n'k d reke lk/kuk dk >kd jgh g vkj vke turk d fy, tudY;k.k dh lfo/kkvk e dVkrh djd] jktxkj d Bdkdj.k dk c<kok ndj] vke turk ij dgj <gk jgh gA turk lxfBr gk çfrjk/k u dj blfy, lkEçnkf;d o tkrh; vk/kkj ij turk dk vkil e yMku d ç;kl gk jg gA ,l e n'k d VM ;fu;u vkUnkyu u fnYyh e 9 l 11 uocj dk egkiMko dk dk;Øe j[kk g ftle yk[kk etnj&depkjh fgLlk yx vkj Hkktik dh dFkuh&djuh dk inkQk'k djxA

vke lHkk dk lhV jkT; egklfpo t;Hkxoku o mik/;{k ljUæ flg] cychj nfg;k] foukn dekj] lj[kk] l[kchj flg] jktdekj] çoh'k dekjh] 'kdryk] jes'k dekj] lj'k dekj] Jhiky HkkVh] djrkj ykgku] jkepUæ vkfn u Hkh lckf/kr fd;kA

ओडिशा

विधान सभा पर जुलूस व धरना

सीटू के स्वतन्त्र अभियान के रूप में निमार्ण, परिवहन, खदान, आशा, मिड–डे–मील आदि सहित संगठित व असंगठित क्षेत्र के हजारों मजदूरों ने राजधानी भुवनेश्वर में रेलवे स्टेशन से राज्य स्तरीय रंगारंग जुलूस निकाला जो मास्टर कामतीन चौक से होता हुआ विधान सभा के सामने पहुँचकर एक रैली व धरने में बदल गया। रैली को सीटू राज्य अध्यक्ष लम्बोदर नायक, महासचिव विष्णु मोहन्ती, उपाध्यक्ष जनार्दनपति, कोषाध्यक्ष दुष्मंतदास, क्योवृद्ध ट्रेड यूनियन नेता व पूर्व विधायक शिवाजी पटनायक, राज्य उपाध्यक्ष व सी पी आइ (एम) विधायक लक्ष्मण मुण्डा, राधारमण सारंगी, उल्हास स्वैन, लोवकांत स्वेन, ईसानी सांरगी, विस्वनाथ महापात्र, रमेश जेना, सत्यानंदा बेहरा व अन्य ने संबोधित किया।

रैली से 26 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया जिसमें मुल्य वृद्धि रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने, 18,000 रूपये न्यूनतम वेतन, बुनियादी श्रम कानूनों को लागू कराने, सभी को कम से कम 3,000 रूपये न्यूनतम पेंशन,समान काम के लिए प्रतिनिधिमंडल इन मांगों को लेकर श्रम मंत्री से मिला जिन्होंने राज्य के न्यूनतम वेतन के पुनर्निधारण के लिए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक सहित अलग–अलग सलाहकार बोर्डो की बैठके बुलाने का भी आश्वासन दिया। *.....(शेष पृष्ठ 13 पर)*

उद्योग व क्षेत्र

कोयला

दसवें मज़दूरी अनुबंध के बारे में

डी. डी. रामानंदन

ऐसा पहली बार हुआ कि सभी पाँच मान्यता प्राप्त कोयला मज़दूर फैडरेशनों द्वारा संयुक्त माँग पत्र दिया गया। जिसमें सी.आइ. टी,यू, ए. आइ.टी.यू, आइ. एन.टी.यू.सी, एच. एम. एस और बी.एम.एस शामिल है। जोकि जे.बी. सी.सी आइ के साथ पिछले 8 महीनों में 9 बार हुई बैठक के बाद संभव हो पाया। फिर भी जैसे ही चर्चा अपने अंतिम चरण में पहुँची भारत कोयला लि० के प्रबंधन ने केन्द्र सरकार और कोयला मंत्री के द्वारा प्राप्त दो असामान्य शर्त रखी जोकि सभी यूनियनों को नागवार थीं।

प्रस्तावित अनुबंध के मुख्य बिन्दु

- पी.एस.यू.एस के कोयला मज़दूर अनुबंधों से भिन्न यह अनुबंध केवल 5 साल के लिए है।
- इस अनुबंध में कम से कम 20% सुनिश्चित लाभ होगा।
- भत्ते में बढ़ते क्रम को 15% – 20% के दायरे में रखा गया है।
- पेंशन फण्ड में प्रबंधकों द्वारा दिया जाने वाले योगदान जोकि वर्तमान में मूल वेतन का 1.16% + महँगाई भत्ता है, को बढ़ाकर 7% कर दिया है।
- प्रबंधकों द्वारा सेवानिवृत्ति स्वास्थ्य सुविधा फण्ड में 1% का योगदान दिया जायेगा, जिसका निर्माण और संचालन संस्था में प्रबंधकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के न्यास के द्वारा किया जायेगा ।
- 01.07.2016 को 10वें मज़दूरी अनुबंध का प्रभारी पूर्वालोकन किया कि कोयला उद्योगों में न्यूनतम वेतन रुपये 30,000/– होगा, और भत्तों के जोड़ से यह वेतन रुपये 36,000/– हो जायेगा।
- ठेका मज़दूरों के लिए निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर सहमति हुई है :

  – कि प्रबंधक व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक समिति का गठन किया जायेगा जिसका उद्देश्य ठेका मज़दूरों के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिए गए निणर्यों को प्रभारी ढ़ग से लागू करना होगा।

  – तथा इसके अलावा एक और समिति का गठन मज़दूरी के पुनः अवलोकन व मज़दूरों की सुरक्षा हेतू किया जायेगा।
- इस अनुबंध के लागू होते ही सी.आइ.एल पर अतिरिक्त वित्तिय भार पहले साल में रुपये 6,000/– करोड़ हो जायेगा।
- यह अनुबंध डी.पी.ई के मार्गदर्शन से बेहतर है।

जब दोनों पक्ष अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए सहमत हो गये थे तभी सरकार के कहने पर प्रबंधक द्वारा दो शर्तों की पेशकश की गई, पहली नौकरी देने के बारे में और दूसरी साप्ताहिक अवकाश के बारे में।

वर्तमान में चार श्रेणियों में भर्ती होती है जोकि दूसरे उद्योगों में उपलब्ध नहीं है। उत्तराधिकारियों को नौकरी के लिए प्रावधान –

1) कर्मचारी के काम ना कर पाने की स्थिति में
2) कोयला खानों में दुर्घटना होने के कारण कर्मचारी की मृत्यु होने पर
3) सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु
4) ज़मीन खोने के कारण उत्तराधिकारी को नौकरी

5) सरकार स्थायी नौकरियों पर भर्ती पर पाबन्दी लगाना चाहती थी।

साप्ताहिक छुट्टी पर – लगातार उत्पादन के उद्देश्य से छुट्टी के अलग अलग समय रखना चाहती है। सभी केन्द्रिय श्रम संगठनों में प्रबंधकों के प्रस्ताव का विरोध किया व समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना किया। प्रबंधकों ने 18 सितंबर तक का समय माँगा। यदि प्रबंधको द्वारा इन दो प्रथम शर्तों पर ज़ोर दिया जाता है तो कोयला फैडेरेशन के पास अन्तिम रास्ता राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल करना हो सकता है।

कोयला प्रबंधकों के ढुलमुल रवैये माँग पत्र के उद्देश्यपूर्ण चर्चा को रोकने के लिए शुरु से ही देखी गई थी। सीटू फैडरेशन द्वारा इस आंदोलन को तेज करने के लिए स्वतंत्र रूप से जुलूस, प्रदर्शन और धरना, पुतला फूँकने आदि का नेतृत्व लिया गया। फिर बाद में, सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा साथ मिलकर आन्दोलन को आगे बढ़ाया गया और हड़ताल के लिए समीक्षा पत्र पेश किया। तब कहीं जा कर जे.बी.सी.सी.आई बैठकीय चर्चा के लिए तैयार हुए। उसके बाद, प्रबंधकों द्वारा मज़दूरी अनुबंध पर नयी शर्तों को थोपने की कोशिश से कर्मचारियो का गुस्सा नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था।

वाहन निर्माण क्षेत्र

मोटर वाहन निर्माण मजदूरों के बीच कार्य

17 सितम्बर 2017 को सीटू ने वाहन निर्माण क्षेत्र में कार्यरत यूनियन की बैठक चैनेई में की। इस बैठक में बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माण कंपनियों में कार्यरत 12 यूनियनों के नेताओं ने शिरकत की। सीटू के अखिल भारतीय नेतृत्व में से कॉमरेड हेमलता, तपन सेन, ए एस सौदंराजन और मीनाक्षी सुन्दरम ने हिस्सा लिया। हेमलता ने बैठक की अध्यक्षता की और तपन सेन ने इस क्षेत्र में तालमेल बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। एस सौन्दराजन और मीनाक्षी सुन्दरम ने इस क्षेत्र में मजदूरों के बीच काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताया।

बैठक में इस क्षेत्र के मजदूरों के हालात के बारे में चर्चा हुई और राष्ट्रीय पैमाने पर तालमेल करने और अन्दोलन करने का निर्णय भी लिया। हेमलता ने समापन और तमिलनाडु राज्य कमेटी का बैठक की मेजबानी के लिए धन्यवाद किया।

स्कीम वर्कर्स

आई सी डी एस योजना को समाप्त करने की कोशिश के खिलाफ

राष्ट्रव्यापी विरोध और पुतला दहन कार्यक्रम

सीटू की आंगनवाड़ी वर्कस और हैल्पर्स की अखिल भारतीय फेडरशन (आइफा) ने केन्द्रिय सरकार के उस निर्णय की भर्त्सना की जिसके वो आंगनवाड़ी केन्द्रों में बने ताजे खाने के बजाए डिब्बों में बन्द खाना देना चाहते है और सीधा कैश खाते में डालना चाहते है। इस फैसले के साथ महिला बाल विकास मंत्री ने अपमान जनक तरह से यह भी कह दिया कि 20 साल पहले ही आंगनवाड़ी एक प्रभावशाली वितरण प्रणाली का दर्जा खो चुकी थी। उनका यह कथन साक्षो और रिपोर्टस से बिल्कुल उलट है। गंभीर कुपोषण और बच्चों की मृत्यु संख्या में भारी कमी होने के बारे में विश्व स्तर पर आई सी डी एस की सराहना हुई है।

यह रूप भाजपा द्वारा आंगनवाड़ी को कमजोर करना और फिर बंद करने की मन्शा को दर्शाता है ताकि आई सी डी एस में खाद्य जगत के महाकाय करपोरेटों को लगाया जाए। हमें याद है कि पहले भी एक वाण्जिय मंत्री ने पेपसीको कम्पनी को आंगनवाड़ी केन्द्र में डिब्बे बन्द खाना देने का निमंत्रण दिया था। सत्ता में आने के बाद से भाजपा सरकार आई सी डी एस को कमजोर (विघटित)

करने के लिए अलग–अलग हथकडे अपना रही है जैसा कि बजट में भारी कटौती, पेंसा देने के तरीके में बदलाव और ताजा बना हुआ खाना मुहैया करवाने की जगह सूखा राशन देना इत्यादि।

ठसके इलावा, 26 लाख आंगनवाड़ी वर्करस और हैल्पर्स जोकि गरीबो और सामाजिक उत्पीड़न के शिकार दायरे से है उनकी व सभी महिलाए है कि नौकरीयां भी खतरे में होगी। ऑल इडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्करस एण्ड हैल्परर्स ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 22, 23, सिंतम्बर को राष्ट्रव्यापी विरोध और सरकार का पुतला दहन के लिए आह्वान किया है।

बीड़ी

अखिल भारतीय बीड़ी वर्कर्स फेडरेशन का 7वाँ सम्मेलन

सीटू के अखिल भारतीय बीड़ी वर्कर्स फैडरेशन का 7वाँ सम्मेलन; 14 से 16 सितम्बर को बैगलोर, तमिलनाडु में हुआ। सम्मेलन में रैली के बाद जन सभा जिसका उद्घाटन केरल राज्य के श्रम मंत्री टी. पी. रामाकृष्णन के द्वारा किया गया। बैठक की अध्यक्षता तमिलनाडु बीड़ी वर्कर्स फैडरेशन के प्रधान, एम. पी. रामाचंद्रन ने की और महासचिव के. थीरूसेलवन ने स्वागत किया।

सीटू के अखिल भारतीय नेता ऐ के पद्मानाभन, ए सौदराजन, माल्ती चिट्टीबाबू, तथा बीड़ी फैडरेशन के नेतागण मंच पर विराजमान थे। रामाकृष्णन ने बीड़ी वर्कर्स पर अन्याय के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि बीड़ी मजदूरों की कोई न्यूनतम वेतन भविष्य निधि ा पेंशन इत्यादि उपलब्ध नही है। उनके रिहायसी मकान और स्वास्थ्य लाभ में भी निरंतरता नही है। केन्द्र की बीजेपी सरकार गरीब जिससे गरीब बीड़ी वर्कर्स बेरोजगार होगे और उनके लिए कोई विकल्प तैयार भी नही किया जा रहा।

मो. निजामुदीन मंच में डेलीगेटस सत्र हुआ जिसका उद्घाटन ए. के. पद्मनाभन ने किया। महासचिव देवाशिश रॉय ने सचिव की रिपोर्ट पेश की और कोषाअध्यक्ष पारसवासु ने लेखा जोखा पेश की। 34 डेलीमेट्स ने रिपोर्ट में बहस में हिस्सा लिया। महासचिव के उत्तर के बाद रिपोर्ट औा लेखा–जोखा सर्वसममिति से पारित हुआ। डेलीगेट्स सेशन को माल्ती चिटाबाबू एस. काशी विश्वानाथ, महासचिव, एटक, तमिलनाडु ने बधाई दी। ऐ. के. पदमानाभन ने समापन भाषण रखा। सम्मेलन में 68 सदस्य कमेटी के साथ के. पी. महादेवन, प्रधान देवशशि रॉय, महासचिव और विमल सान्याल को कोषाअध्यक्ष चुना।

आई टी

बंगलुरू में आई टी कर्मचारियों की यूनियन का गठन

20 अगस्त 2017 को आई टी और आई टी ई एस में कार्यरत कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बैंगलरू के वाई उव्लूपू सी ए हाल में बैठक करके आई और आई टी एस इम्पलाईज यूनियन का गठन किया। सीटू राज्य कमेटी के उप–प्रधान और एक अनुभवी मजदूर नेता वी जे के नायर ने सभा में शिरकत और मार्गदर्शन किया। बैठक ने यूनियन का सविंधान बनाया और यूनियन के 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत पंजीकृत (रजिस्टर) करने का संकल्प किया। सभा ने सात सदस्य पदाधिकारी और 14 सदस्यों को कार्यकारणी के लिए चुना। साथी अमनुलाखन को अध्यक्ष, वीनीत विकल को महासचिव, संदीप डी आर को कोषाध्यक्ष चुना।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा औद्योगिक संबंध विधेयक संहिता का कड़ा विरोध

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा ट्रेड यूनियन एक्ट, औद्योगिक विवाद एक्ट व स्टैंडिग आर्डर एक्ट को हटा कर उनके स्थानों पर लाये जाने वाली औद्योगिक संबंध विधेयक संहिता के मसविदे पर चर्चा के लिए बुलाई गयी एक बैठक में, ट्रेड यूनियनो के संयुक्त मंच में शामिल सभी 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने संहिता मसौदे का पूरी तरह और विरोध करते हुए हस्ताक्षर युक्त एक संयुक्त बयान दिया जिसमें प्रस्तावित कोड को मजदूरों व ट्रेड यूनियनों के बुनियादी अधिकारों पर कुठाराघात करने, हड़ताल के अधिकार पर एक तरह से पूरी पांबदी लगाने तथा 95 प्रतिशत से ज्यादा श्रम शक्ति को अपने दायरे में लेने वाले सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों को मनमरजी से मजदूरों को लगाने और हटाने की ताकत देने वाले ''लगाआ और हटाओ निजाम'' को अमल में लाने के लिए बनाया गया कोड बताया। बैठक में उपस्थित सभी ट्रेड यूनियनों ने विधेयक का विरोध किया तथा ट्रेड यूनियनों की राय/सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसके फिर से तैयार किये जाने की माँग की।

बैठक में शिरकत कर रहे सीटू महासचिव तपन सेन ने संयुक्त बयान में दर्ज मुद्दों की चर्चा करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि औद्योगिक संबंध विधेयक पर संहिता के मसविदे और वेतन विधेयक 2017 पर संहिता (जिसे संसद में पेश किया जा चुका है) दोनों में ही ''मजदूरों'' और '' कर्मचारियों'' की परिभाषा के मामले में एक साजिश रची जा रही है। परिभाषा को इस रूप में गढ़ा गया है ताकि नियोक्ता, मजदूरों के एक अच्छे–खासे हिस्से को दोनों ही विधेयकों के बहुत से प्रावधानों के दायरे को दोनों ही विधेयकों के बहुत से प्रावधानों के दायरे से बाहर रख सकने में सफल रहें; ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिसमें मजदूरों के एक हिस्से को ''सुपरवाइजर'', ''मैनेजर'' आदि का नाम देकर प्रावधानों की सुरक्षा से वंचित रखा जा सके।

यही नही, परिभाषाओं को इस प्रकार बनाया गया है कि नियोक्ता ''सेल्स प्रोमोशन कर्मचारियों'' को एक्ट के दायरे में आने से वंचित कर सकते हैं। यहाँ तक कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (जे) (ii) (बी) के तहत मौजूदा प्रावधान को, जो सेल्स प्रोमोशन कर्मचारियों को मजदूर के रूप में मान्यता देता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल के ड्रॉफ्ट से हटा दिया गया है। सेन ने ऐसे प्रावधानों को पूरी तरह से हटाने और विधयेक को पूरी तरह से समावेशी बनाने के लिए उसके मसविदे को फिर से तैयार किये जाने की मांग की।

अंतर्राष्ट्रीय

सीटू प्रतिनिधिमंडल का डब्लू एफ टी यू के मुख्यालय का दौरा

के० हेमलता

सीटू के 15 वें सम्मेलन के तुरन्त बाद डब्लू एफ टी यू ने सीटू के नेतृत्व को अपनी सुविधा अनुसार डब्लू एफ टी यू मुख्यालय में आने का निमन्त्रण दिया। तदा अनुसार कॉमरेड हेमलता प्रधान, कॉमरेड तपन सेन – महासचिव, तथा कॉमरेड स्वदेश देव रॉय सीटू के अखिल भारतीय सचीव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के इंर्चाज के, एक प्रतिनिधिमंडल ने 5 से 8 सितम्बर 2017, को एथेन्स का दौरा किया। सीटू के प्रतिनिधि मंडल का डब्लू एफ टी यू के केंद्र कार्यालय के मुख्य संयोजक अन्दा अनासतासकी ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। होटल में डब्लू एफ टी यू के महासचिव जोर्ज मावरिकोस तथा वरिष्ठ नेता वेलेन्टटिनों पाचो ने प्रतिनिधमंडल का स्वागत किया और कार्यक्रम के बारे में सूचित किया ।

इसी दौरान साउथ अफ्रिका ट्रेड यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल जोलाजपेथा वहां कि राष्ट्रीय शिक्षा स्वास्थ्य और सहियोगी मजदूर यूनियन नेशनल यूनियन ऑफ हेल्थ वर्कर्स के महासचिव डेविट सीपूंजी और पुलिस एन्ड सरविल राइट यूनियन के महासचिव के साथ डब्लू एफ टी यू के प्रधान माईकल मेक माईवा भी डब्लू एफ टी यू के मुख्यालय में सीटू के प्रति निधिमंडल से मिले ।

6 सितम्बर की सुबह सीटू का प्रतिनिधि मंडल डब्लू एफ टी यू के मुख्यालय गया वहा उपस्थित कॉमरेडो को स्मृति चिन्ह भेंट किए तथा र्जाज मावरिकोस से बातचीत की। उन्होने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए कहा कि सीटू के इस दौरे से डब्लू एफ टी यू और सीटू के अंतर्राष्ट्रीय हालात और मजदूर वर्ग की स्थिति के बारे में समझ और पुख्ता होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन और भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन को निश्चित तौर पर मदद मिलेगी।

डब्लू एफ टी यू के महासचिव ने कहा की विश्व के सभी महाद्वीपो और दूनिया के सभी कोनो में हालात बहुत जटिल है। डब्लू एफ टी यू और इसके क्षेत्रीय कमेटिया ऐशिया पेसिपिक कमेटि के सहित हालात पर गहरीनजर रखे हुए है डब्लू एफ टी यू की अक्टूबर 2016 में साउथ अफ्रिका में 7वीं कांग्रेस हुई थी। पूंजीवादी वर्ग इस संकट का सारा बोझ मजदूर वर्ग पर डाल रहा है। दूनिया भर में मजदूर वर्ग इन हमलों को रोकने का प्रयास कर रहे है लेकिन मजदूर वर्ग की संधर्षो को कमजोर करने के लिए उनको बांटने व अलग–थलग करने का प्रयास कर रहा है। अलग–अलग देशों की दूतावास अपने देशों के प्रवासी मजदूरों को मजदूर वर्ग की मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास कर रहे है।

उन्होंने डब्लू एफ टी यू के अंर्तराष्ट्रीय सर्वहारा और मजदूर वर्ग को पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संगठित करने का व्योरा दिया। डब्लू एफ टी यू के इन प्रयासों से डब्लू एफ टी यू का प्रभाव अलग– अलग देशों और महाद्विपों में बढ़ रहा है। इसकि एक खास उदाहरण डब्लू एफ टी यू अफ्रिका और लेटिन अमेरिका में बढने हुए प्रभाव में बताया गया। ट्रेड यूनियन इंटरनैशनल जिसकी बैठक अक्सर डब्लू एफ टी यू मुख्यालय में , होती है इस बार 9–10 अक्टूबर को कोलकाता में होगी। इन सभी दायरों में डब्लू एफ टी यू का विस्तार हो रहा है। बहुत सारी कठनाईयों के वावजूद डब्लू एफ टी यू यूरोप में शक्ति शाली बनने का गंभीर प्रयास कर रहा है। इस कार्य की जिम्मेदारी ग्रीक की ट्रेड यूनियन पामे को दी गई है।

मावरिकोस ने डब्लू एफ टी यू के आने वाले समय के अंर्तराष्ट्रीय प्रोग्राम की सूचना भी दी। 3 अक्टूबर का अंर्तराष्ट्रीय कार्य दिवस प्रवासी और शरणार्थियों के मुद्दों पर मनाने की जानकारी भी दी। 25 और 26 अक्टूबर को पेरिस में दवा उद्योग और स्वाथ्य का अंर्तराष्ट्रीय समेलन किया। यंग वर्कस का सम्मेलन इटली में होगा। महान अक्टूबर क्रांति की शताब्दी के अवर्सर पर डब्लू एफ टी यू दूनिया में संदेश देना चाहता है।

कामगार महिलाओं की एशिया पेशिपिक सम्मेलन की तैयारी के लिए वेतनाम में 6 और 7 दिसम्बर में और कामकाजी महिलाओं की कांग्रेस 8 मार्च 2018 को पनामा में होगी।

मेवरिकोस ने सीटू को इन सम्मेलनों में प्रतिनिधि मंडल भेजने का आग्रह किया। कॉमरेड हेमलता और तपन सेन ने डब्लू एफ टी यू को का निमंत्रन के लिए धन्यवाद किया और भारत के मजदूर वर्ग की स्थिति, सीटू की पहल कदमी पर संर्धष तथा संयुक्त मजदूर आंदोलन को अवगत कराया। उन्होने संयुक्त ट्रेड यूनियन के आहवान पर 9 से 11 नवम्बर के संसद समक्ष महापड़ाव के बारे में बताया।

डब्लू एफ टी यू की बैठक के बाद पामे जो कि ग्रीस का जुझारू मजदूर आंदोलन है के सचिव–मंडल के साथ बातचीत हुई जिसकी अगुआई ग्रीओरग्रीओस पेरेस ने की। ग्रीओरग्रीओस पेरेस ने वहा की सरकार के विकास और वृद्धि के बहाने मजदूरों के उपर हमलों का जिक्र किया। वहा की सरकार मजदूरों के हड़ताल के अधिकार के उपर पावन्दि लगाने के लिए कानून बनाने का प्रयास कर रही है और मजदूर वर्ग के सामूहिक आंदोलन रोकने का प्रयास कर रही है। पिछले तीन सालों में मजदूरों के वेतन में 40 प्रतिशत की कटौती, 10 लाख मजदूरों को 3 महिनों से लेकर 1 साल तक वेतन का भुगतान नही किया गया। 1 साल के भितर हालात सुधरने का हवाला देते हुए मजदूरों को शान्तिपूर्वक इन्तजार करने को कहा गया।

वेरोजगारी 30 प्रतिशत और नौजवानों की बेरोजगारी 55 प्रतिशत हो चुकी है। इन सभी हमलों के खिलाफ अलग– अलग क्षेत्रों के मजदूर पामे के नेत्रित में आंदोलन कर रहे है। 9 सितम्बर को फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि 40 कापरेट के साथ ग्रीस में पधार रहे है उनके खिलाफ बहुत सारे सहरों में पामे ने प्रर्दशनों का फैसला लिया है। उन्होंने बताया की पामे एक और हड़ताल की तैयारी कर रही है और को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ कर आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होने बताया कि सरकार कम्यूनिस्ट विरोधी तथा राष्ट्रीयवादी विचार पनपा रही है ताकि लोगों को सरकार की जनविरोध नितियों के गुस्से से भरकाया जाए। साम्राज्यवादी युद्ध की स्थिती में पामे वहा के मजदूर वर्ग अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के अनुसार साम्रवाद के खिलाफ खड़ा होना। पामे तुरकिस्तान के मजदूर वर्ग से भी इसी पर बात–चीत कर रहा है।

अपनी प्रस्तुति का समापन करते हुए पेरोस ने कहा कि बड़े मालिकों, सरकार और ऐसी यूनियनें जो बड़े मालिकों और सरकार के नियंत्रण में हैं, व मुकावला करने की परेशानी के होते हुए भी, पामें ए की सफलता के प्रति आशावान है। वे इस विश्वास से प्रोत्साहित हैं कि श्रमिक वर्ग कम भविष्य वर्वर पूँजीवादी व्यवस्था और मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं हो सकता। इस का संबन्ध भूत काल से है और इसे वहीं (भूतकाल) में धकेल देना चाहिए।

7 सितम्बर को सी आई टी यू के प्रतिनिधि दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ एथेन्स के कैसीयानी क्युकनकस पैलिटी में डब्लू एफ टी यू के स्थापक नेता की याद में बनाए गए स्मारक पर जाकर पुष्पंजलि अर्पित कि। उन्होंने, उनके ठहरने एवं ट्रेड यूनियन और ग्रीस के अन्य नेताओं से बात–चीत करने का बढ़िया प्रबन्ध करने के लिए डब्लू एफ टी यू के प्रधान कार्यालय का धन्यवाद किया।

व्यापार और विकास पर यू एन सी टी ए डी रिपोर्ट 2017 का सार

विश्व आर्थिक व्यवस्था असंतुलित है जो न केवल गैर समावेशी है बल्कि वो अस्थिर भी है जो राजनैतिक, सामाजिक और वातावरण की सहेत के लिए घातक है।

इसके लाभ विशेष लोगों के लिए हैं। वैश्विक आर्थिक संकट के समय 10 साल पहले जो खर्च कटौती योजनाए लागू हुई उनके हालात और खराब हुएं । इन योजनायों ने दुनिया के गरीब लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है जिससे लोगो का धुर्विकरण किया और लोगों की भविष्य में उनके हालात क्या होंगे के लिए चिन्ताओं को बढ़ावा दिया।

कुछ विशिष्ट राजनैतिक वर्ग इस बात पर अड़े हैं कि इसका कोई विकल्प नही है। जो कि मांगने के विकल्प के तैयार किया। अन्य लोगों ने प्रौधोगिक या व्यापार को बहिष्कार और व्यापक भूमंडलीकरण को दोषी ठहराया। लेकिन यह असली विन्दु भटकाने वाली है।

क्योंकि यह वैश्विक मांग को बढ़ाने के लिए एक खास तालमेल रहित तरीके की वकालत ही हैं। वेतन वृद्धि और सरकारी खर्चो के बढ़ौतरी के बिना विश्व के अर्थव्यवस्था मंदी की दौर से बाहर नही निकल सकती।

2017 की ट्रेड और डिवेलपमेंट रिपोर्ट का कहना है, कि सख्त और व्यापक कदम उठाने की जस्रत है जिससे दुनिया और देशों के संसाधन जुटाना तकनिकि जानकारी, बाजार की क्षमता, तय व्यापक भूमंडली करण वहिपकरण से पैदा के हालात को और खराब कर देगा। अगर सही कदम न उठाए गए। *(14 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित अंकटेड रिपोर्ट की भूमिका का अंश)*

कामकाजी महिलाओं के लिए सीटू का कार्यभार

13 जुलाई 2017 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित कामकाजी महिला समन्वय समिति एवं 14–16 जुलाई को शिमला में ही आयोजित सीटू की कार्यसमिति बैठक में पारित आगामी कार्य –

1. तीन माह के भीतर, सभी राज्यों में राज्य स्तरीय कामकाजी महिला समन्वय समितियां गठित करें। सीटू कमेटियां सुनिश्चित करें कि संबंधित कामकाजी महिला समन्वय समितियों की प्रभावी बैठकें आयोजित की जाएं।
2. अधिवेशन के अनुसार, सीटू से संबंधित सभी यूनियनें व इसकी फैडरेशनें, जिनमें महिला व पुरूष दोनों सदस्य हों, में महिला उप समितियों का गठन करें ताकि इस क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की विशेष समस्याओं पर चर्चा की जा सके। महिला कार्यकर्ताओं का विकास कर, उन्हें पदोन्नत करके निर्णायक मंडलों में लाने के लिए उचित कार्यक्रम आयोजित करें।
3. अधिवेशन के निर्णय के अनुसार, कामकाजी महिला समन्वय समितियों की बैठकें व सीटू राज्य कमेटी ''कामकाजी महिलाएं – एक वर्गीय दृष्टिकोण' कमिशन पेपर पर अवश्य चर्चा करें।
4. सभी राज्य कामकाजी महिला समन्वय समितियां कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा करें और बिरादराना सब कमेटियों में चर्चा करें।
5. कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न' विषय पर आयोजित की गई कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करना।
   - राज्य व जिले स्तर पर ऐसी ही कार्यशालायें करना;
   - बिरादराना ट्रेड यूनियनों – ए आइ एस जी इ एफ, सी सी जी इ डब्ल्यू, बेफी, ए आइ आइ ए, बी एस एन एल इ यू आदि की सब कमेटियों के साथ संयुक्त अभियान;
   - सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में शिकायत कमेटियों की मौजूदगी के बारे में सर्वेक्षण करना;
   - कार्यालयों, फैक्टरियों, प्रतिष्ठानों व संगठित/ असंगठित क्षेत्र के विभिन्न सैक्टरों में संबद्ध यूनियनों/ बिरादराना ट्रेड यूनियन संगठनों के बीच जागृति अभियान;
   - इस मुद्दे से निपटने के लिए प्रभावी मशीनरी की मांग को सीटू यूनियनों के माँगपत्र में शामिल करना;
   - कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका तैयार करना;
6. कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति के निर्णय के अनुसार–

1. कामकाजी महिलाओं के बीच बड़ी संख्या में अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की 11वीं कन्वेंशन में पारित कामकाजी महिलाओं के मांगपत्र को प्रचारित करना। राज्य व जिला स्तरों पर कामकाजी महिलाओं के आम मांगपत्र तैयार करने के लिए संयुक्त अभियान जारी रखना, हस्ताक्षर अभियान चलाकर सितम्बर 2017 तक जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपें।
2. राज्य स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन कक्षा। हिन्दी भाषी राज्यों की राज्य स्तर की महिला कार्यकर्ताओं (जिसमें स्कीम वर्कर शामिल नहीं हैं) के लिए केंद्र स्तर पर ट्रेड यूनियन कक्षा
3. 'वॉयस ऑफ द वर्किंग वुमन' व 'कामकाजी महिला' का कोटा संपूर्ण करें। प्रत्येक राज्य में एक व्यक्ति को रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी दी जाए।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdk vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dsn	tu 2017	जुलाई 2017
vk/k izns'k	xa.Vwj	274	276
	gSnjkckn	246	250
	fo'kk[kkiÿku	276	280
	okjaxy	286	291
vle	MeMek frulf[k;k	259	259
	xokgkVh	244	247
	ycd flYpj	259	259
	efj;kuh tkjgkV	241	243
	jxkikjk rstiqj	238	239
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	294	297
p.Mhx<	p.Mhx<	273	279
NÿhlxZ<	fHkykbZ	310	311
fnYyh	fnYyh	252	263
Xkkvk	xkvk	298	297
Xkqtjkr	vgenkckn	267	274
	Hkkouxj	266	269
	jktdkV	270	272
	lwjr	259	263
	oMknjk	259	261
gfj;k.kk	Qjhnkckn	258	262
	;euk uxj	272	275
fgekpy	fgekpy çn'k	250	257
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	260	263
>kj[k.M	ckdkjk	300	306
	fxfjMhg	325	337
	te'kniqj	302	307
	>fj;k	319	326
	dkMek	312	323
	jkph gfV;k	287	291
dukVd	cyxke	286	291
	cxykj	297	301
	gcyh /kkjokM	296	301
	ejdjk	297	299
	eSlwj	291	294
djy	,.kkdqye@vyobZ	302	302
	eq.MkD;ke	322	326
	fDoyku	271	279
e/; çn'k	Hkksiky	281	287
	fNnokM+k	255	261
	bUnkSj	277	281

jkT;	dsn	tu 2017	जुलाई 2017
egjk"V	eEcbZ	290	293
	ukxiqj	312	318
	ukfld	291	293
	iq.kZ	274	276
	'kksykiqj	295	296
mMhlk	vkxy&rkypj	297	298
	jkmjdsyk	292	296
ikfMpfj	ikfMpfj	295	301
iatkc	verlj	276	285
	tkyU/kj	276	279
	yf/k;kuk	272	276
jktLFkku	vtesj	257	263
	HkhyokM+k	272	279
	t;iqj	264	274
rfeyukMq	pUuS	263	266
	dks;EcVwj	267	270
	dUuwj	285	287
	enqjkbZ	279	284
	lqyse	271	274
	fr#fpjkiYyh	286	291
f=iqjk	f=iqjk	296	296
mÿkj çn'k	vkxjk	251	254
	xkft;kckn	303	308
	dkuiqj	270	278
	y[kuÅ	286	291
	okjk.klh	278	285
if'pe cxky	vklulky	277	286
	nkftfyax	302	307
	nxkiqj	256	256
	gfYn;k	301	308
	gkoM+k	307	314
	tkyikbZxqM+h	269	270
	dksydkrk	268	268
	jkuhxat	264	269
	flyhxqM+h	245	255
		256	261
vf[ky Hkkjrh; lpdk		280	285

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्क:** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेल: citubtr@gmail.com
  फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

गौरी लंकेश की हत्या

बंगलुरू में विशाल विरोध रैली

(रिर्पोट पृ० 8)

बैंकों के निजीकरण व विलय के खिलाफ

संसद के सामने बैंक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन

रिर्पोट पृ० 11)

बैंक कर्मियों को संबोधित करते सीटू महासचिव तनप सेन

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/15-17 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2015-2017 (Date of Publication - 5/10/2017)

राजस्थान में राज्यव्यापी किसान आंदोलन

(रिपोट पृ० 9)

सीकर में विशाल किसान रैली

लाल पोशाक में मार्च का नेतृत्व करती महिलाएं

'मृत' राज्य सरकार की 'अंत्येष्टि'

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : **के हेमलता**

असम

गुजरात

पंजाब

महाराष्ट्र

रायकोट, पंजाब

महाराष्ट्र

कोलकाता

नोएडा (एन सी आर)

अमृतसर, पंजाब

नई दिल्ली

गुवाहाटी, असम

रोपड़ , पंजाब